प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

****

ए. नीतिगत पहल:

(क) एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025

खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम] को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से संशोधित किया गया है। इसके माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

i. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र और प्रादेशिक सीमा बढ़ा दी गई है ताकि ट्रस्ट को प्राप्त निधियों का उपयोग भारत के भीतर, उपयुक्त क्षेत्रों सहित, और भारत के बाहर खानों एवं खनिजों के अन्वेषण एवं विकास के लिए किया जा सके। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट' कर दिया गया है ताकि इसके विस्तृत कार्यक्षेत्र को दर्शाया जा सके। वकीलों द्वारा ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली राशि वर्तमान 2% रॉयल्टी से बढ़ाकर 3% कर दी गई है।

ii. अधिनियम में किसी भी नए खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रमुख खनिजों को लघु खनिजों को खनन पट्टे में भी शामिल किया जा सकता है, अगर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए। खनिजों को शामिल करने के लिए, अधिनियम की नई आठवीं अनुसूची में अतिरिक्त देय राशि निर्दिष्ट की गई है। अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-डी में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और कार्मिक सुधारों या अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सुधारों को शामिल करने पर कोई अतिरिक्त राशि लागू नहीं होती है, ताकि इन खनिजों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं और जिनमें खनन और प्रसंस्करण कठिन होता है।

iii. खनन पट्टे (प्रत्यावयन) या मिश्रित लाइसेंस (सीएल) के अंतर्गत क्षेत्र का एक बार विस्तार राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भुगतान पर किया जा सकता है, जिसमें एक सन्निहित क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। यह भुगतान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। एमएल के मामले में, सन्निहित क्षेत्रधारक या लाइसेंस के तहत आने वाले क्षेत्र के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और सीएल के मामले में, सन्निहित क्षेत्र पट्टे या लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे गहराई में स्थित खनिजों के खनन को बढ़ावा मिलेगा, जो सन्निहित क्षेत्रों में छिपे हुए हैं और हो सकता है कि उन्हें अलग पट्टे या लाइसेंस के अंतर्गत निकालना आर्थिक रूप से व्यवहारिक न हो।

iv. केंद्र सरकार को मिनरल एक्सचेंज के ज़रिए खनिजों, उनके कंसंट्रेट या उनके प्रसंस्कृत रूपों (धातु सहित) के बाज़ार और व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। मिनरल एक्सचेंज स्थापित करने से खनिकों और खनिजों के अंतिम उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति और मांग के आधार पर सही और पारदर्शी बाज़ार कीमतें तय करने, बाज़ारों को स्थिर करने और बजट बनाने और योजना बनाने में मदद मिलेगी।

v. कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर लगी सीमा हटा दी गई है। अब खनिक खान से जुड़े एंड यूज़ प्लांट की ज़रूरत पूरी करने के बाद और अधिनियम में बताई गई अतिरिक्त राशि का भुगतान करके खनिज बेच सकते हैं। इसके अलावा, खनिकों को उन डंप को बेचने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा बताई गई तारीख तक कैप्टिव लीज़ में जमा किया गया है और जिनका कैप्टिव इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे खनिक खनिज संसाधनों का बेहतर खनन सुनिश्चित कर पाएंगे, पर्यावरण खतरों को कम कर पाएंगे और खानों में सुरक्षा बढ़ा पाएंगे, बाज़ार में खनिजों का उत्पादन और सप्लाई बढ़ा पाएंगे और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

vi. इसके अतिरिक्त, अधिसूचित खनिजों जैसे बॉक्साइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैंगनीज के खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की पूर्व तैयारी की आवश्यकता को हटा दिया गया है, ताकि नीलामी में तेजी से लाई जा सके।

(ख) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन

एमएमडीआर अधिनियम के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाए और अधिसूचित किए गए हैं:

i. कैलिब्रेटेड लैंप अयस्क की परिभाषा में संशोधन और मासिक एवं वार्षिक रिटर्न के प्रारूपों में संबंधित बद्लाव के लिए जी.एस.आर. 232(ई) दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया।

ii. खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 को जी.एस.आर. 255(ई) दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जिसमें सहायक कंपनी की होल्डिंग कंपनी की कुल संपति को खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने के लिए कुल संपति मानदंडों के प्रावधान हेतु विचार करने की अनुमति दी गई, चाहे होल्डिंग कंपनी भारत में निगमित हो या भारत के बाहर।

iii. खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025 को जी.एस.आर. 382(ई) दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के दुर्लभ धातु और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरी) निक्षेपों के लिए अन्वेषण मानदंड शामिल किए गए थे, जैसे कि पेग्माटाइट, रीफ, शिराओं और अन्य यौगिकों आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले आरी, जो सारणीबद्ध और लेंस के आकार के होते हैं। नियमों में जी4/जी3/जी2 चरण में विभिन्न प्रकार के निक्षेपों के लिए अन्वेषण के अंतर्गत ये मानदंड शामिल हैं।

iv. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 को जी.एस.आर. 486(ई) दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसमें सीज़ियम, ज़िरकोनियम और रुबिडियम खनिजों के एएसपी की गणना की विधि निर्दिष्ट की गई थी।

(ग) अन्य सुधार

i. एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3 के खंड (ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एस.ओ. 924 (ई) दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज खनिजों को लघु खनिजों की सूची से हटा दिया। ये खनिज अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के साथ पाए जाते हैं और इनके महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग हैं।

ii. खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20ए के तहत दिनांक 01.05.2025 को आदेश जारी किया, ताकि बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और गढ़वाल के निवासियों के खनन पट्टियों को लघु खनिजों से प्रमुख खनिजों की श्रेणी में परिवर्तित किया जा सके।

iii. केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित नियमों में संशोधन किया है:

क. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. के माध्यम से। 780(ई) दिनांक 23.10.2025।

ख. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 776(ई) दिनांक 22.10.2025 के माध्यम से।

iv . केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 764(ई) दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, नीलाम की गई खानों के संचालन में तेजी लाने के लिए मध्यवर्ती समयसीमाएं लागू की गई हैं। मध्यवर्ती समयसीमाएं नीलाम की गई खानों के संचालन की प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करती हैं, जो आशय पत्र जारी होने से लेकर खनन पट्टिकाएं निष्पादित होने तक के विभिन्न चरणों में लागू होती है। समयसीमाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क. प्राधिकृत नियम आशय पत्र जारी होने से लेकर खनन पट्टिका/समग्र लाइसेंस के लिए नीलाम किए गए ब्लॉकों के लिए पट्टिका/लाइसेंस विलेख निष्पादित होने तक विभिन्न लक्ष्य और उनकी समयसीमाएं निर्धारित करते हैं।

ख. बोलीदाता के कारण निर्धारित समय सीमा के देरी होने पर, हर महीने या उसके हिस्से के देरी के लिए निष्पादन सुरक्षा का 1% आवंटन किया जाएगा। हालांकि, यदि अंतिम लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है, तो पहले हुई देरी के लिए लगने वाले किसी भी जुर्माने को नीलामी प्रीमियम में समायोजित कर दिया जाएगा।

ग . इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर पसंदीदा बोलीदाता को आशय पत्र जारी नहीं करती है, तो अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि प्रत्येक माह या माह के अंश के विलंब के लिए 5% कम हो जाएगी।

घ . देरी/समयसीमा का पालन न करने की स्थिति में, राज्य सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशक (डीएमजी) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें राज्य के राजस्व विभाग, राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग और आईबीएम के सदस्य शामिल होंगे, पसंदीदा बोलीदाता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निर्णय लेगी। केवल तभी जुर्माना लगाया जाएगा जब देरी बोलीदाता के कारण हुआ हो।

च . इसके अतिरिक्त, नीलाम की गई खानों से उत्पादन शीघ्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। ठेकेदार को उत्पादित खनिजों के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के भीतर या समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तिथि से सात वर्षों के भीतर नीलामी प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना आवश्यक है।

v. केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 786(ई) दिनांक 23 अगस्त, 1989 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 751(ई) दिनांक 10.10.2025 द्वारा अधिकृत किया है, जिसमें चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

vi. केंद्र सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो को एम.एम.डी.आर. अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में सुसंगत खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के लिए खनिज विनिमय पंजीकृत करने और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण नियुक्त किया है, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4570(ई) दिनांक 07.10.2025 द्वारा।

vii. केंद्र सरकार ने आदेश दिनांक 16.10.2025 द्वारा निम्नलिखित पांच नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के लिए आशय पत्र (एल.ओ.आई.) की वैधता बढ़ा दी है:

i. गुगुलदोह मैंगनीज अयस्क ब्लॉक (मास्क)
ii. पारशिवनी/पारसेओनी मैंगनीज ब्लॉक
iii. हमदरा-घोड़ेपाइपवाड़ी बॉक्साइट ब्लॉक
iv. लोहारडोंगरी लौह अयस्क ब्लॉक
v. सुरजागढ़-3 लौह अयस्क ब्लॉक

viii. केंद्र सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं कार्यभार) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में 20.11.2025 से प्रभावी संशोधन किया है जिसमें सीज़ियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और ज़िरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी अनुमानित निर्धारित की गई हैं। विवरण नीचे दिया गया है

क्रम संख्या	खनिज	रॉयल्टी की दरें
1 .	सीजियम	उत्पादित अयस्क में मौजूद सीज़ियम धातु पर, सीज़ियम धातु की औसत बिक्री कीमत का दो प्रतिशत शुल्क लगेगा।
2	ग्रेफाइट i. 80% या उससे ज़्यादा कार्बन ii. 80% से कम सस्ता कार्बन	 मूल्य के आधार पर औसत विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत मूल्य के आधार पर औसत विक्रय मूल्य का 4 प्रतिशत
3	रूबीडियम	उत्पादित अयस्क में निहित रुबिडियम धातु पर लगने वाला रुबिडियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत
4	ज़र्कोनियम	उत्पादित अयस्क में निहित ज़िरकोनियम धातु पर औसत विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत परिमाण होगा।

(घ) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं भूगोल) संशोधन अधिनियम, 2023

i) भारत के संविधान का अनुच्छेद 297 उपयुक्त क्षेत्रों में सभी एंटीऑक्सीडेंट को केंद्र सरकार के अधीनस्थ करता है। संसद ने उपयुक्त क्षेत्रों में खनिज आईएएस के विकास और पैदल चलना के के लिए ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 बनाया, जिसमें भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।

ii) ओएएमडीआर अधिनियम, भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधन के विकास और विनियम और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामला के के लिए आउटलुक करता है।

iii) ओएएमडीआर अधिनियम 2002 को ओएएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से 17.08.2023 से संशोधित किया गया था। उक्त संशोधन के ज़रिए, अन्य बातों के अलावा, आण्विक खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के लिए प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ़ प्रतिस्पर्धी बोली के ज़रिए नीलामी द्वारा प्रोडक्शन लीज़ देने का प्रावधान किया गया।

(ई) ओएएमडीआर अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान/नियमों के निर्माण की स्थिति

ओएएमडीआर अधिनियम के तहत 2025 में निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं:

i. **अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025** को जी एस आर 311(E) दिनांक 14.05.2025 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, ताकि खनिज ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के लिए कुल संपति मानदंडों के उद्देश्य से सहायक कंपनी की होल्डिंग कंपनी की नेट वर्थ पर विचार करने की अनुमति दी जा सके, भले ही होल्डिंग कंपनी भारत में या भारत के बाहर निगमित हो।

ii. अपतटीय क्षेत्रों में आण्विक खनिजों के संचालन के अधिकार संबंधी नियम, 2025 को जी एस आर 468(E) दिनांक 14.07.2025 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम सरकार, एक सरकारी कंपनी या एक निगम को परमाणु भौतिकी के संबंध में संचालन अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

बी. नीलामी और जिला खनिज कोष (डीएमएफ) की स्थिति:

नीलामी और संचालन की स्थिति:

(i) 2015 में नीलामी प्रणाली शुरू होने के बाद से, देश में 585 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इनमें से 368 ब्लॉकों की नीलामी खनन पट्टे (ML) के लिए और 217 ब्लॉकों की नीलामी मिश्रित लाइसेंस (CL) के लिए की गई है। इसके अलावा, 94 ब्लॉकों के लिए खनन पट्टे निष्पादित किए गए हैं, जिनमें से 79 चालू हैं। 84 ब्लॉकों के लिए मिश्रित लाइसेंस विलेख निष्पादित किए गए हैं

(ii) 2025 में, मंत्रालय ने खनिज संसाधन विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 05.12.2025 तक कुल 141 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इसमें खनन पट्टिका (एमएल) के लिए नीलाम किए गए 79 ब्लॉक और समग्र लाइसेंस (सीएल) के रूप में दिए गए 62 ब्लॉक शामिल थे। 2015 में नीलामी प्रणाली शुरू होने के बाद से यह एक वर्ष में नीलाम किए गए ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या है, जो तेज प्रक्रिया और राज्यों तथा उद्योग की मजबूत भागीदारी को दर्शाती है। विशेष रूप

से, असम और उत्तराखंड ने इस अवधि के दौरान पहली बार खनिज ब्लॉकों की नीलामी की, जिससे भारत के नीलामी मानचित्र में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई।

(iii) कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने क्रमशः 33 और 22 ब्लॉकों की नीलामी की है, जो सबसे अधिक संख्या है। आंकड़ों में, चूना पत्थर की नीलामी सबसे अधिक (41) हुई, उसके बाद लौह अयस्क (32) और बॉक्साइट (22) का स्थान रहा। नीलाम किए गए ब्लॉकों का राज्यवार सारांश नीचे दिया गया है।

राज्य	नीलाम हुए खनिज ब्लॉकों की संख्या *
मध्यप्रदेश	32
राजस्थान	22
छत्तीसगढ़	18
गुजरात	18
कर्नाटक	12
आंध्रप्रदेश	8
ओडिशा	8
असम	7
तेलंगाना	2
उत्तरप्रदेश	2
उत्तराखंड	1
गोवा	1
केंद्र सरकार	10
कुल	141

*5 दिसंबर 2025 तक

(iv) वर्ष 2025 के दौरान अब तक, नीलाम किए गए 24 ब्लॉकों को ऑपरेशन में लाया जा चुका है। 2025 में, मंत्रालय ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के ऑपरेशन में तेजी से लाने पर विशेष बल दिया, और प्रक्रिया को मजबूत और तेज करने के लिए कई उपाय किए। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

प्रगति बैठक: प्रगति के तहत उच्च स्तर पर नीलामी और क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है; लक्षित हस्तक्षेपों के लिए राज्यों को (A/B/C) में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के अधीन 03.04.2025 और 17.11.2025 को समीक्षा बैठकें की गई।

सचिव (खान) द्वारा मासिक समीक्षा : सचिव (खान) ने नीलामी किए गए ब्लॉकों के संचालन की प्रगति की निगरानी करने और समग्र प्रगति में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए वर्ग- ए राज्यों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें शुरू की हैं।

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू): खनिज ब्लॉकों को तेजी से क्रियान्वयन में लाने के लिए 15.01.2025 से मंत्रालय में एक समर्पित पीएमयू स्थापित किया गया है। पीएमयू , अन्य बातों के अलावा, खनिज ब्लॉकों को मुआवजा बनाने के लिए अग्रिम प्रक्रिया को कार्यान्वित करने, अनुमोदन की लगभग वास्तविक समय की स्थिति बनाए रखने, सफल बोली लगाने वाले को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करने, सरकारी निकायों के साथ कार्यभार का समन्वय करने और आवंटन आवेदनों की शीघ्र जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य गाजियाबाद के विभिन्न सर्वेक्षणों के साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है।

व्यक्तिगत समीक्षा बैठकें: राज्य और केंद्र स्तर पर नियमित रूप से उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और उनकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री या सचिव (खान) करते हैं, जिसमें

सभी प्रमुख हितधारक शामिल होते हैं। अब तक, विभिन्न राज्यों में 13 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

खनन डैशबोर्ड की शुरुआत: नीलामी किए गए खनिज ब्लॉकों, संबंधित मंजूरी और देरी की लगभग वास्तविक समय में ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए 04.06.2025 को एक खनन डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। यह डैशबोर्ड एलओएल जारी करने, लीज डीड के निष्पादन और वैधानिक अनुमोदन (ईसी/ एफसी) प्रदान करने जैसे प्रमुख लक्ष्यों की निगरानी करके खनिज ब्लॉकों को परिचालन बनाने में तेजी से लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक और निजी दोनों में यह विस्थापन और जवाबदेही को उन्नति है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ी निगरानी को सक्षम बनाता है। आंकड़े प्राप्त करना और निगरानी को और परिस्थितियों करने के लिए डैशबोर्ड को एक एकीकृत वेब पोर्टल में भी अग्रसर किया जा रहा है। इस डेटा-संचालित दृष्टिकोण से बाधाओं की सक्रिय रूप से पहचान करने, समय पर हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करने और राज्यों में खनिज ब्लॉकों को परिचालन बनाने में काफी तेजी से लाने की उम्मीद है।

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

a. 2015 में, खान और खनिज (विकास और आधुनिकीकरण) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ एक नई धारा 9 बी जोड़ी गई जो खनन कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान करती है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित ऑपरेशन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए उस तरीके से काम करना है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। डीएमएफ को खनन पट्टा धारकों से वैधानिक योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

b. सितंबर 2015 में, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी एम के के वाई) बनाई जिसे डीएमएफ द्वारा लागू किया जाना था और, सरकार ने, राष्ट्रीय हित में, एम एम डी आर अधिनियम, 1957 की धारा 20 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे डी एम एफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करें और उक्त योजना को लागू करें।

c. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई) को संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा प्राप्त धन का उपयोग करके लागू किया जा रहा है। पीएमकेकेकेवाई योजना के समग्र उद्देश्य हैं-

(क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाएं/कार्यक्रम को लागू करना. ये योजनाएं/कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाएं/परियोजनाओं के पूरक होंगे;

(ख) खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान और बाद में होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/खतम करना; और

(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

d. डी एम एफ अब 23 राज्यों के 656 जिलों में स्थापित किया गया है, जो पहले के 646 जिलों के आंकड़ों से अधिक है, जो महत्वपूर्ण विस्तार और पहुंच को दर्शाता है।

e. दूसरा राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन (डी एम एफ) की कार्यशाला का आयोजन 9 जुलाई, 2025 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और जिलों के बीच आपसी सीख को बढ़ावा देना, योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना, और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। इस कार्यशाला में 300 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें केंद्र और राज्य के मंत्रालयों के प्रतिनिधि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी, प्रमुख डीएमएफ, जिलों के एसडीएम और गैर-लाभकारी संगठन शामिल थे। इसमें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) पर चर्चा हुई, और राज्य और जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीतियों पर भी बात हुई।

I. सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी और माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे ने उद्घाटन भाषण दिया। आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए संचालन दिशानिर्देश शुरू की गई, जो खान मंत्रालय द्वारा लक्षित डीएमएफ हस्तक्षेपों के माध्यम से आकांक्षी ब्लॉकों में विकास और समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीएमएफ में सर्वोत्तम रुझानों को उजागर करने वाली एक पुस्तक का भी अनावरण किया गया।

II. कार्यशाला के हिस्से के रूप में, हैंडलूम हाट, जनपथ, दिल्ली में डीएमएफ-समर्थित स्वयं सहायता समूहों (ग्रामीण विकास) की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम उत्पादों को प्रदर्शित किया गया और स्वयं सहायता समूहों को ग्राम विकास दिखाने, आगंतुकों से जुड़ने और संभावित बाजार संबंधों की पहचान करने का अवसर प्राप्त हुआ।

F. डीएमएफ समर्थित स्वयं सहायता समूहों ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2025 के दौरान खनन मंडप के भीतर समर्पित स्टालों पर अपने आठ उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों की क्षमताओं और उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया, जिससे उन्हें आगंतुक से जुड़ने, अपनी शिल्प को बढ़ावा देने और नए बाजार संपर्क तलाशने का अवसर मिला। 14 से 27 नवंबर, 2025 तक, डीएमएफ समर्थित 23 स्वयं सहायता समूहों ने, 7 खनन प्रभावित राज्यों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए, राष्ट्रीय मंच पर भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्रों के प्रामाणिक स्वाद, शिल्प और कलात्मकता का प्रदर्शन किया।

G. अक्टूबर 2025 तक, डीएमएफ के तहत कुल 120602 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए हैं, जिसमें से 100911 करोड़ रुपये पीएमकेकेवाई के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 64426 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इनमें से 64426 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस योजना के तहत कुल 421072 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 251296 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं।

सी. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के लिए ₹16,300 करोड़ का वित्तीय परिव्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और अन्य उपक्रमों से ₹18,000 करोड़ के अनुमानित निवेश की उम्मीद है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की सतत, स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर आधारभूत ढांचे, प्रसंस्करण और समाप्ति हाने वाले उत्पादों से खनिजों तक के सभी चरण शामिल हैं।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को खान मंत्रालय के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक, सात वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाएगा-

"भारत के 2047 विकसित भारत के सफर पर आगे बढ़ने के साथ ही, देश की प्रगति में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और समाप्ति होने वाले उत्पादों से खनिजों तक के सभी चरण शामिल हैं। एनसीएमएम का लक्ष्य नीतिगत सुधारों, वित्तीय सहायता, अवसंरचना सुविधाएं, मानव संसाधन विकास, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से एक समग्र कार्य योजना विकसित करना है। सरकार का उद्देश्य भारत के लिए एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थिति तंत्र बनाना है।"

मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को मज़बूत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज तेजी से शुरु कर दी है। जीएसआई ने 2025-26 में देश भर में 230 महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, एनएमईडीटी ने 2025-26 के दौरान (अब तक) महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ii. खान और खनिज विकास अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 अधिनियम में एनएमईडीटी के दायरे का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया ताकि विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण और खनन का समर्थन किया जा सके।

iii. खान मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के 34 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

iv. मंत्रालय ने खनन लाइसेंस के 7 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिनमें से 3 रणनीतिक खनिजों के हैं।

v. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माध्यमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा 02.10.2025 को जारी किए गए और योजना शुरू की गई।

vi. ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मैड आदि से महत्वपूर्ण खनिज निकालने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता के लिए निर्देश 14 नवंबर 2025 को जारी किए गए।

vii. खान मंत्रालय ने एनसीएमएम के अंतर्गत नौ प्रमुख संस्थानों को पोषक केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है ताकि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) किया जा सके और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में घरेलू उद्देश्यों को मजबूत किया जा सके। प्रत्येक पोषक केंद्र

(सीओई) एक कंसोर्टियम के रूप में, हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है, ताकि घटक उद्योग और अकादमी स्पोक्स की मुख्य क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

अन्य गतिविधियां

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण सेमिनार–

भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा 6 जून 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत चल रहे उपक्रमों के हिस्से के रूप में 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संगोष्ठी' का आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान जनजातियों के वरिष्ठ निकायों को आमंत्रित किया गया ताकि सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, तकनीकी ज्ञान साझा किया जा सके और लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार को गति प्रदान की जा सके। घरेलू प्रसंस्करण इकाइयां, राज्य सरकारों की भूमिका, उद्योग-नेतृत्व वाले नवाचार और प्रचलित रणनीतियों पर केंद्रित चर्चाओं के माध्यम से, संगोष्ठी का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाना और देश को एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सीआरएम क्षेत्र की ओर ले जाने में सहायता करना था।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन आउटरीच फोरम का शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एन सी एम एम) आउटरीच फोरम का शुभारंभ किया। यह फोरम सरकारी निकायों, उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान विद्यार्थियों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है।

इस मंच का उद्देश्य नीतिगत संवाद, अनुसंधान, निवेश और उद्योग विकास को बढ़ावा देना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र की अहम भूमिका पर प्रकाश डालना है। श्री रेड्डी ने सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और निजी कंपनियों सहित सभी खनिजों से भारत में एक मजबूत और टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज खनिजों तंत्र के निर्माण में सक्रिय रूप से निवेश करने, नवाचार करने और भाग लेने का आह्वान किया। खान मंत्रालय और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के नेतृत्व में, यह मंच महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है और खनन क्षेत्र के स्थायी और रणनीतिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ।

महत्वपूर्ण खनिजों पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आई एम जी)

महत्वपूर्ण खनिजों पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की चौथी बैठक 20 मार्च, 2025 को खान मंत्रालय के सचिव श्री वी. एल. कंथा राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य

महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक समग्र रणनीति तैयार करने और उसे समर्थन देने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना था। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (पीएसयू), राज्य के मंत्रियों, मंत्रालयों, निजी कंपनियों और अनुसंधान जनजातियों के प्रतिभागियों ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग किया।

खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी)

खनिज सुरक्षा साझेदारी एक महत्वाकांक्षी नई अमेरिकी नेतृत्व वाली बहु व्यक्तिपरक साझेदारी है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। जून 2023 में, भारत एमएसपी का नवीनतम साझेदार (14वां सदस्य देश) बना, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर विविध और टिकाऊ महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को गति देना है। साथ ही, भारत ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों सहित एमएसपी के सिद्धांतों को स्वीकार किया। नवंबर 2025 में एमएसपी टीम द्वारा 40 परियोजनाओं की एक सूची साझा की गई थी। खान मंत्रालय ने ब्राजील में लीथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एक भारतीय परियोजना (अल्टीमिन द्वारा) की सिफारिश खनिज सुरक्षा साझेदारी को की थी। यह परियोजना अब एमएसपी परियोजना सूची में शामिल कर ली गई है। इससे भारतीय उद्योगों के लिए खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

4 दिसंबर 2025 को, खान मंत्रालय के सचिव, श्री पीयूष गोयल, आईएएस ने, आईईए की उप कार्यकारी निदेशक, सुश्री मैरी वारलिक के साथ महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में सहयोग को मजबूत करने, डेटा-आधारित सहयोग को बढ़ाने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए संयुक्त अवसरों की खोज पर चर्चा की।

सम्मेलन/कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ-

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने विदेश मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से 13 नवंबर 2025 को 15वें "ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन" का आयोजन किया। खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विवेक कुमार बाजपेयी ने महत्वपूर्ण संकेतकों पर विशेष सत्र का नेतृत्व किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक सतत और कम कार्बन कार्य वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों पर व्यापक चर्चा को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (एन एम ई डी टी)

• खनन एवं खनिज (विकास एवं नियामक) अधिनियम 1957 की धारा 9 C द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने 14 अगस्त, 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन एम ई टी) की स्थापना की और मानदंडों और संबंधित गतिविधियों की क्षेत्रीय और विस्तृत खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 बनाए।

• हाल ही में, खनन एवं खनिज (विकास एवं नियामक) संशोधन अधिनियम, 2025 ने एन एम ई टी में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ट्रस्ट का नाम अब राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (एन एम ई टी) कर दिया गया है ताकि भारत और विदेश दोनों में खनन और खनिज विकास को शामिल करने के लिए इसके बढ़ते हुए जनादेश को दिखाया जा सके।

• एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 सी के प्रावधानों के तहत, ट्रस्ट का दायरा बढ़ाया गया है ताकि भारत के भीतर उपयुक्त क्षेत्रों में खोज के लिए कोष और भारत तथा विदेशों में निर्धारित तरीकों से खदानों और मानकों की क्षेत्रीय और विस्तृत खोज और विकास को शामिल किया जा सके।

• संशोधन नेतृत्त्वदार के योगदान को भी रॉयल्टी के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया है, जिससे ट्रस्ट की वित्तीय क्षमता बढ़ेगी ताकि बड़े और अधिक उन्नत खोज पहलों का समर्थन किया जा सके।

• ये बदलाव राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, ताकि भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

उपलब्धियाँ-

• एनएमईडीटी को ₹855.31 करोड़ का योगदान मिला है।

• एनएमईडीटी ने ₹560.56 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली 156 परियोजनाओं को मंजूर दी है, जिनमें से 130 खनिज अन्वेषण की, 08 परियोजना खरीद की, 17 परियोजना एस एंड टी प्रिज्म की और 01 परियोजना आईबीएम द्वारा माइन्स के नमूनों के भू-रासायनिक विश्लेषण के लिए विशेष अध्ययन से संबंधित है।

• 130 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं में से, 57 परिशिष्ट अधिसूचित निजी अन्वेषण यौगिकों (एनपीईए) को स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31 महत्वपूर्ण मानदंडों से और 26 गैर-महत्वपूर्ण मानदंडों से संबंधित हैं।

• एनएमईडीटी ने राज्यों और केंद्रीय आवास/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां को उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए 08 परियोजनाओं के लिए ₹182.79 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

• एनएमईडीटी के खोजे गए 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।

• एस एम ई टी की स्थापना 08 राज्यों यानी असम, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और सिक्किम में की गई। इससे संबंधित राज्यों में छोटे खनिजों की खोज को और बढ़ावा मिलेगा।

• खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए 7 राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, तेलंगाना, असम और छत्तीसगढ़) को ₹7.0 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

• एनएमईडीटी खान मंत्रालय की एस एवं टी पीआरआईएसएम योजना के तहत अनुसंधान और विकास को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्त पोषण में सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त अवधि के दौरान, एनएमईडीटी ने खान मंत्रालय की एस एंड टी प्रिज्म योजना के तहत ₹23.56 करोड़ की स्वीकृत लागत वाले 17 प्रोजेक्ट्स को वित्त पोषित किया है।

• पूर्वी क्षेत्र में खनिज अन्वेषण की गति बढ़ाने और खनन एवं भूविज्ञान निदेशालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान व्यवस्थित अन्वेषण करने के लिए प्रत्येक एनईआर राज्य को ₹10 करोड़ की वित्तीय सहायता शुरू की गई।

• एनएमईडीटी ने देश भर में खदान के फेसेस, मिनरल स्टैक, डंप, टेलिंग, प्रोसेस मटेरियल और स्मेल्टर स्लैग से सैंपल के जियोकेमिकल एनालिसिस के लिए ₹12.80 करोड़ की एक स्पेशल स्टडी को फंड दिया है, ताकि एक भरोसेमंद राष्ट्रीय स्तर का जियोकेमिकल डेटाबेस विकसित किया जा सके और खदान पश्चिम में महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता का आकलन किया जा सके।

• ओवरबर्डन/टेलिंग/फ्लाई ऐश/रेड मैड आदि से महत्वपूर्ण खनिज निकालने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश 14.11.2025 को पेश किए गए थे, जिसका उद्देश्य माइन टेलिंग, डंप आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली को बढ़ावा देना, माध्यमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की अधिकतम प्राप्ति को प्रोत्साहित करना, खनिज प्राप्त करने के लिए नवोन्मेष तकनीक विकसित करना और उनका व्यवसायीकरण करना और कम ग्रेड के जटिल खनिजों के लिए हाइड्रोमेटलर्जी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल बायो-हाइड्रोमेटलर्जी, उन्नत वसूली तकनीक आदि जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है।

• माननीय केंद्रीय खान मंत्री द्वारा 4 मार्च, 2025 को कोलकाता में जीएसआई की 175वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सात आरएमटी योजनाओं का प्रस्ताव एनपीईए को सौंपा गया। इन सात ब्लॉकों में से, पांच क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण ब्लॉक को विभिन्न एनपीईए को ₹39.62 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी दी गई है। इससे महत्वपूर्ण खनिजों के अधिक अन्वेषण ब्लॉक बनेंगे।

ई. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संक्षिप्त गतिविधियां-

<u>समझौता ज्ञापन/सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और हस्तांतरण किया गया:</u>

(i) एमसीएलआर और कैटामार्का प्रांत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 19.2.2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और हस्तांतरण किया गया। यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अर्जेंटीना के कैटामार्का में खनिज अन्वेषण परियोजनाओं की पहचान और निष्पादन के लिए सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करना है।

(ii) खान मंत्रालय, भारत सरकार और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई), जापान के बीच खनिज आधारभूत के क्षेत्र में एक सहयोग ज्ञापन एमओसी) पर 28.08.2025 को साइन किए गए। एमओसी का हस्तांतरण टोक्यो, जापान में 29.08.2025 को किया गया।

(iii) खान मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय, मंगोलिया के बीच "भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग" पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 14.10.2025 को भारत में हस्ताक्षर किए गए और हस्तांतरण किया गया।

(iv) खान मंत्रालय, भारत सरकार और बोलीविया के बहुराष्ट्रीय राज्य की सरकार के बीच भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के विस्तार के प्रोटोकॉल पर 24.10.2025 को बोलीविया में हस्ताक्षर किए गए।

<u>संयुक्त कार्य समूह की बैठकें:-</u>

भूविज्ञान और खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच पहली संयुक्त कार्य समिति की बैठक ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 28.01.2025 से 30.01.2025 तक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री वी. एल. कंथा राव, सचिव, खान मंत्रालय ने किया।

द्विपक्षीय बैठकें:

(i) माननीय केंद्रीय खान और कोयला मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और महामहिम श्री बंदर अलखोरयेफ, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री, सऊदी अरब साम्राज्य के बीच 04.02.2025 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। चर्चा के दौरान, सऊदी पक्ष ने जीएसआई और सऊदी विश्लेषक सर्वे के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और जीएसआईटीआई को स्तंभ केंद्र के रूप में नामित करने के लिए अपने मंत्रालय के सकारात्मक इरादों की चर्चा की। चर्चा में स्थायी खनिज अन्वेषण और खनन के लिए उन्नत विधियों को प्रोत्साहन में सहयोग पर भी विचार किया गया।

(ii) माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने 15.02.2025 को नई दिल्ली में श्रीलंका सरकार के उद्योग और उद्यमिता विकास मंत्री श्री सुनील हंडुनेट्टी के साथ एक बैठक की। श्रीलंका में भारतीय उद्यमिता द्वारा ग्रेफाइट, समुद्र तट रेत आदि की संभावित अन्वेषण और खनन गतिविधियों पर चर्चा की गई।

(iii) माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 19.2.2025 को नई दिल्ली में अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर महामहिम श्री राउल जलील के साथ एक बैठक की। चर्चा खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से लीथियम की खोज और निवेश के अवसरों पर केंद्रित थी।

(iv) भारत सरकार के खान मंत्रालय के सचिव और श्रीलंका सरकार के उद्योग और उद्यमिता विकास मंत्रालय की सचिव सुश्री जे.एम. थिलाका जयसुंदरा के बीच 10.03.2025 को एक आभासी बैठक हुई। चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, समुद्र तट की रेत और फॉस्फेट की खोज और खनन में भारत के लिए अवसर और भूविज्ञान और खनिज क्षेत्र में सहयोग पर भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना शामिल थी।

(v) खान मंत्रालय के सचिव ने 20.03.2025 को भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त, महामहिम फिलिप ग्रीन के साथ एक बैठक की और ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण आंकड़ों की खोज और खनन के अवसरों, काबिल-सीएमओ एमओयू, आदि पर चर्चा की गई।

(vi) माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 01.04.2025 को नई दिल्ली में भारत-चिली खनन उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान चिली की खान मंत्री

महामहिम सुश्री ऑरोरा विलियम्स के नेतृत्व में चिली प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। खनन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को गहन करने पर चर्चा की गई।

(vii) भारत सरकार के खान मंत्रालय के सचिव और भारत में पेरू के राजदूत महामहिम श्री जेवियर पॉलिनिच के बीच 05.06.2025 को नई दिल्ली में खनन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई। राजदूत ने बताया कि पेरू में मोलिब्डेनम, तांबा, आयरन अयस्क और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिजों की अच्छी क्षमता है। साथ ही, राजदूत ने भारतीय प्रतिनिधियों को, भारतीय उद्योगों के फैलाव के साथ, पेरू में 22-26 सितंबर, 2025 तक होने वाले एक प्रमुख खनन कार्यक्रम पेरू मिन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

(viii) खान मंत्रालय के सचिव और मलावी के माननीय खान मंत्री डॉ. केन ज़िखाले न्ग'ओमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के बीच 28.08.2025 को नई दिल्ली में खनन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों और दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन के संशोधन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई।

(ix) 13.11.2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार के खान मंत्रालय के सचिव और रूसी संघ के व्यापार और उद्योग उप मंत्री श्री एलेक्सी ग्रुजदेव के बीच एक बैठक हुई। चर्चा का मुख्य विषय महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था।

(x) 17.11.2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार के खान मंत्रालय के सचिव, नीदरलैंड साम्राज्य के विदेश मंत्रालय की व्यापार और आर्थिक सुरक्षा सचिव सुश्री यवेट वैन ईचौड और भारत में नीदरलैंड साम्राज्य की राजदूत सुश्री मारिसा गेराड्र्स के बीच एक बैठक हुई। चर्चा का मुख्य विषय प्रोसेसिंग, लोडिंग, स्टॉकपाइलिंग आदि सहित एक स्थायी और टिकाऊ खनिज मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल पर धोनी सहयोग था।

(xi) 26.11.2025 को माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें भारत और कनाडा के बीच खनन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। कनाडाई प्रतिनिधियों का नेतृत्व कनाडा के उच्चायुक्त श्री क्रिस्टोफर कूपर ने किया। चर्चा का मुख्य विषय महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग शुरू करना था, जिसमें मूल्य-श्रंखला में अवसरों सहित सभी पहलुओं पर बात हुई।

विभिन्न देशों में की गई खोज:

(i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने 03.03.2025 से 07.03.2025 तक सोमालीलैंड में खनिज अन्वेषण से संबंधित गतिविधियां की। एकत्रित किए गए नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि यह क्षेत्र भू वैज्ञानिक रूप से उपजाऊ है और इसमें सोना, लिथियम और संबंधित खनिजीकरण की संभावना है।

(ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण और परामर्श लिमिटेड के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 25.06.2025 से 29.06.2025 तक टोही यात्राएँ करने और 15.9.25 से 31.10.25 तक ज़ाम्बिया के कैसेम्पा प्रांत में वैज्ञानिकों के मानचित्रण से संबंधित प्रश्नावली करने के लिए ज़ाम्बिया का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय समूह में भागीदारी

(i) खान मंत्रालय के सचिव श्री वी. एल. कंथा राव के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 25 अप्रैल, 2025 तक लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप (आईएलजेडएसजी) और इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप (आईसीएसजी) 2025 की अध्यक्षता में भाग लिया। भारत आईसीएसजी और आईएलजेडएसजी दोनों का सदस्य है। हर साल, ये समूह प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों, केस स्टडी आदि पर चर्चा/साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें करते हैं।

(ii) भारत जून, 2025 में इंटरनेशनल निकेल स्टडी ग्रुप (आईएनएसजी) में एक सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। इंटरनेशनल निकेल स्टडी ग्रुप (आईएनएसजी) एक स्वायत्त, अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और यह लिस्बन, पुर्तगाल में स्थित है। आई एनएसजी के सदस्य निकल उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापार करने वाले देशों की सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अन्य अंतर-सरकारी संगठन हैं।

<u>खनन क्षेत्र में भारत की क्षमताओं, रुचि और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खनन कार्यक्रमों में भागीदारी :</u>

(i) केंद्रीय खान और कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 14.01.2025 से 16.01.2025 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 'फ्यूचर मिनरल फोरम' में भाग लेने के लिए सऊदी अरब गए।

(ii) श्री संजय लोहिया, अतिरिक्त सचिव, खान मंत्रालय के नेतृत्व में एक भारतीय सम्मेलन ने कनाडा के टोरंटो में 2.03.2025 से 5.03.2025 तक प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा (पीडीएसी) में भाग लिया, जो दुनिया का प्रमुख खनिज अन्वेषण और खनन सम्मेलन है, और खनिज अन्वेषण से जुड़े लोगों, कंपनियों और संगठनों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।

<u>एफ. खान मंत्रालय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम</u>

(i) खनिज के निष्कर्ष में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, गति और दक्षता के अत्यधिक महत्व को पहचानते हुए और इसे व्यवहारिक आर्थिक मिश्र धातुओं और धातुओं में बदलने के लिए, राष्ट्रीय खनिज नीति ने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी है। भारत सरकार का खान मंत्रालय अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है।

(ii) 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, खान मंत्रालय ने खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत अकादमी पुस्तकों, पाठ्यक्रमों, राष्ट्रीय पुस्तकों और अनुसंधान एवं विकास पुस्तकों से एक बार प्रस्ताव आमंत्रित किए। सत्यभामा पोर्टल पर कुल 221 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईएसएम, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं, जेएनआरडीसी, जेएनयू अन्य जैसे प्रमुख मतदाताओं से 42 परियोजनाओं को ₹22.65 करोड़ की स्मारक के लिए चुना गया है। ये प्रस्ताव कॉन्सेप्ट का सबूत (पीओसी) है और टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (टीआरएल) 3 से 7 तक हुए हैं, और उनके सफल परिणामों से खनन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने की उम्मीद है, जैसे कि महत्वपूर्ण तत्वों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, धातुओं, भूविज्ञान और अन्वेषण, डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्रों में,

और औद्योगिक इकाइयों के प्रभावी उपयोग से गैर-लौह खंड में चक्रीय अर्थव्यवस्था और निस्तारण को बढ़ावा मिलेगा। 42 परियोजनाओं में से, 13 (पीओसी) परियोजनाएं हैं जिनमें उद्योग की भागीदारी नहीं है, प्रत्येक की अधिकतम सीमा ₹10 लाख है। शेष 29 परियोजनाओं में, उपयोगकर्ता उद्योग जुड़े हुए हैं और इन आर एंड डी परियोजनाओं से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ₹3.87 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(iii) इसके अलावा, 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए, खान मंत्रालय ने खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के एस एंड टी - पीआरआईएसएम घटक के तहत कंटेनर्स/एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर्स से एक बार प्रस्ताव आमंत्रित किए। सत्यभामा पोर्टल के अंतर्गत 57 उत्कृष्टता केंद्र में से कुल 6 परियोजनाओं को 7.58 करोड़ रुपये की राशि के लिए चुना गया है।

<u>एनसीएमएम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)</u>

i. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एन सी एम एम) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को एक खनिज पहल के रूप में बढ़ाया था, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू क्षमता विकसित करना और आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाना है। एन सी एम एम के तहत दिशानिर्देश 16 अप्रैल 2025 को जारी किए गए थे। इसके बाद, योग्य संस्थानों को आवेदन के लिए 28 अप्रैल 2025 को बुलाया गया था।

(ii) मूल्यांकन और स्वीकृति की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, खान मंत्रालय ने 9 संस्थानों - 4 आईआईटी (आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की), आईआईएससी बैंगलोर और 4 आर एंड डी प्रयोगशालाओं (सी एस आई आर - आईएमएमटी भुवनेश्वर, सी एस आई आर - एनएमएल जमशेदपुर, एनएफटीडीसी, हैदराबाद और सी मेट , हैदराबाद) को एनसीएमएम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी। प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र एक हब और स्पोक मॉडल पर काम करता है, जो महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में एंड-टू-एंड लवण को चलाने के लिए उद्योग भागीदारों और आर एंड डी / अकादमी संस्थानों को एक साथ लाता है।

<u>जी. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)</u>

नाल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हासिल किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(a). वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन की मुख्य बातें:

(I) वित्तीय मुख्य बातें:

- नाल्को ने 16,788 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है।
- नाल्को ने इस साल 5,325 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो FY 2023-24 की तुलना में 158% ज़्यादा है।
- कंपनी 2024 में दुनिया में बॉक्साइट और एल्युमिना उत्पादन में सबसे कम लागत वाली निर्माता की अपनी स्थिति बनाए हुए है।

(II) उत्पादन की मुख्य बातें:

- पंचपतमली बॉक्साइट माइंस ने वित्त वर्ष 2024-25 में शुरुआत से अब तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न बॉक्साइट खनन 76,48,220 MT हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 23-24 में हासिल किए गए पिछले सबसे अच्छे 76,00,230 रुपये टन को पार कर गया है।
- स्मेल्टर प्लांट ने वित्त वर्ष 21-22 से लगातार चौथी बार वित्त वर्ष 24-25 में 4,60,000 रुपये टन कास्ट मेटल प्रोडक्शन की स्थापित क्षमता हासिल की है।
- कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) ने 6,641 एमयू का अब तक का सबसे ज्यादा नेट बिजली उत्पादन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 10-11 में हासिल किए गए पिछले सबसे ज्यादा 6,607 MU को पार कर गया है।

(III) बिक्री की मुख्य बातें:

- वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की शुरुआत से अब तक की सबसे ज्यादा कुल घरेलू मेटल बिक्री 4,54,600 रुपये टन हासिल की, जो वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले सबसे ज्यादा 4,38,876 रुपये टन से ज़्यादा है।

(b). वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन की मुख्य बातें:

(I) H1 तक की वित्तीय मुख्य बातें:

- ऑपरेशन से रेवेन्यू एच 1 वित्त वर्ष 2024-25 में ₹6,858 करोड़ से बढ़कर एच 1 वित्त वर्ष 2025-26 में ₹8,099 करोड़ हो गया, जो 18.1% की बढ़ोतरी दिखाता है।
- कर से पहले लाभ (पीबीटी) बढ़कर ₹3,325 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में दर्ज ₹2,254 करोड़ से 47.5% ज़्यादा है।
- कर के बाद लाभ (पीएटी) ₹2,497 करोड़ रहा, जो एच 1 वित्त वर्ष 2024-25 में हासिल ₹1,663 करोड़ पर 50.2% की मजबूत बढ़त दिखाती है – यह कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा H1 पीएटी है।

(II) अक्टूबर'25 तक उत्पादन की मुख्य बातें:

- एल्युमिना रिफाइनरी ने अक्टूबर'25 महीने तक कंपनी की शुरुआत से अब तक का सबसे ज़्यादा कुल एल्युमिना हाइड्रेट्स उत्पादन 13,30,000 MT हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले सबसे ज़्यादा 12,21,000 MT से ज़्यादा है।
- एल्युमिना रिफाइनरी ने अक्टूबर'25 महीने तक कंपनी की शुरुआत से अब तक का सबसे ज़्यादा कुल कैल्साइंड एल्युमिना उत्पादन 13,51,000 मीट्रिक टन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले सबसे ज़्यादा 12,24,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा है।
- स्मेल्टर ने अक्टूबर'25 महीने तक कंपनी की शुरुआत से अब तक का सबसे ज्यादा कुल कास्ट मेटल प्रोडक्शन 2,74,730 करोड़ टन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले सबसे ज्यादा 2,69,396 रुपये टन से ज़्यादा है।

- कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) ने शुरुआत से लेकर अक्टूबर'25 महीने तक 4,018 एमयू बिजली का अब तक का सबसे ज्यादा कुल नेट उत्पादन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2017-18 के पिछले सबसे ज्यादा 3,825 एमयू को पार कर गया है।
- सीपीपी ने शुरुआत से लेकर अक्टूबर'25 महीने तक 4,528 एमयू का अब तक का सबसे ज्यादा कुल उत्पादन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2017-18 के पिछले सबसे अच्छे 4,321 एमयू को पार कर गया है।

(III) अक्टूबर'25 तक बिक्री की मुख्य बातें:

- शुरुआत से लेकर अक्टूबर'25 महीने तक 8,34,789 रुपये टन एल्युमिना की अब तक की सबसे ज़्यादा कुल बिक्री हासिल की, जो वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर'24 महीने तक हासिल की गई पिछली सबसे अच्छी 7,40,513 लीटर टन को पार कर गई।
- शुरुआत से लेकर अक्टूबर'25 महीने तक 2,59,936 रुपये टन धातु की अब तक की सबसे ज़्यादा कुल घरेलू बिक्री हासिल की, जो वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर'24 महीने तक हासिल की गई पिछली सबसे अच्छी 2,59,549 रियायत टन को पार कर गई।

(ग) प्रमुख पुरस्कार और सम्मान :

- पंचपटमाली बॉक्साइट माइन सेंट्रल और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक माइंस को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आईबीएम) से वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है,
- एल्युमिना रिफाइनरी, एमएंडआर कॉम्प्लेक्स ने ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा स्थापित ग्रीनटेक गतिविधियों एंड मूवमेंट अवार्ड 2025 जीता है। यह पुरस्कार 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रिफाइनरी के उत्कृष्ट प्रदर्शन और गुणवत्ता के प्रति समर्पण की मान्यता में प्रदान किया गया था।
- कैप्टिव पावर प्लांट को 12 जून 2025 को मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा <250 सेटअप कोयला आधारित श्रेणी में पर्यावरण पशुधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
- नाल्को ने 30 अक्टूबर 2025 को कोलकाता में आयोजित 11वें एशियन खनन कांग्रेस में प्रतिष्ठित "इक्विपमेंट टाइम्स-माइनिंग एंड मिनरल एक्सीलेंस अवार्ड 2025" और "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पीएसयू " पुरस्कार जीता।

एच. **हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (सीसीएल)**

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (**एचसीएल**) ने 1 अप्रैल, 2025 को चिली की सरकारी तांबा खनन कंपनी कोडेल्को (कॉर्पोरेशियन नैशनल डेल कोबरे) के साथ ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि अन्वेषण, खनन और खनिज प्रसंस्करण के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण को अनुकूल बनाया जा सके। इस समझौता ज्ञापन **एचसीएल** पर की ओर से श्री संजीव कुमार सिंह, सीएमडी , और कोडेल्को की ओर से श्री रूबेन अल्वार्डो विगार, सीईओ ने हस्ताक्षर किए।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के एच 1 रिजल्ट 48% बढ़े

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (**एचसीएल**) के बोर्ड ने कोलकाता में हुई अपनी बैठक में चालू वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न श्रेणी-1 सी पीएसई , **एचसीएल** ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ (पी बी टी) में 83.72% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हासिल किए गए 135.33 करोड़ रुपये की तुलना में 248.63 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के दौरान संचालन से कुल राजस्व 718.04 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही की तुलना में 38.57% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही का कर पश्चात लाभ (पी टी) 186.02 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 24-25 की इसी तिमाही की तुलना में 82.95% की भारी वृद्धि है।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान, एचसीएल ने पीबीटी में 47.86% की बढ़ोतरी के साथ अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 289.46 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 427.99 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह, एच 1 वित्त वर्ष 26 में हासिल किया गया कर के बाद का लाभ (पी ए टी) 215.09 करोड़ रुपये से बढ़कर 320.30 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के इसी एच1 की तुलना में 48.91% की बड़ी बढ़ोतरी है। H1 के दौरान कार्य से राजस्व 1234.41 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के एच1 में यह 1011.79 करोड़ रुपये था, जो 22% की अच्छी-खासी बढ़ोतरी है।

एच1 वित्त वर्ष 26 में हासिल किया गया ईबीआईडीटीए 515.32 करोड़ रुपये था। एच1 वित्त वर्ष 25-26 में ईबीआईडीटीए हासिल किया गया अंतर 41.75% रहा, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के एच 1 में यह 37.45% था।

श्री संजीव कुमार सिंह, डिपार्टमेंट-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, एचसीअल ने कहा कि दूसरी तिमाही और एच 1 के नतीजे सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और बढ़ोतरी और सभी स्टेकहोल्डर्स के अटूट समर्थन का सबूत हैं। यह लाभ उत्कृष्ट कार्यकुशलता , लगातार उत्पादन, और पिछले जून 25 के पहली तिमाही वित्त वर्ष 26 तिमाही की तुलना में ज़्यादा वॉल्यूम और धातु की कीमतों के कारण हासिल हुआ है।

भारत उन जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है जो हमारे माइक्रोचिप्स, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्वच्छ ऊर्जा, एल्यूमीनियम सिस्टम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल खनिजों को शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि, ये ज़्यादातर चट्टानों में बंद हैं जिनके उत्खनन के लिए खास खनिज प्रसंस्करण की ज़रूरत होती है। ठोस चट्टानों के खनन में अपनी अनोखी विशेषज्ञता के साथ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) उन कुछ कंपनियों में से एक है जो विशेष खनिज क्षेत्र में कदम रखने और हमारे देश को मूल्यवान सेवा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। इसी दृष्टिकोण के तहत, एचसीएल सीमा से परे देख रहा है। कंपनी ने प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और चिली के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तांबे माइनर कोडेल्को के साथ सहयोग किया है। एचसीएल विदेश में भी विशेष और खनिज संपदा की तलाश कर रहा है।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 का पीबीटी 54% बढ़ा है-

भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न सीपीएसई , हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) का कर से पहले का लाभ (पी बी टी) वित्त वर्ष 2023-24 के 410.43 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 54% बढ़कर 633.51 करोड़ रुपये हो गया है।

27.05.2025 को कोलकाता में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में स्वीकृत ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के अनुसार, एचसीएल ने फाइनेंस वर्ष 2024-25 में ऑपरेशन से अब तक का सबसे अधिक

राजस्व 2070.97 करोड़ रुपये दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 1717.00 करोड़ रुपये से साल-दर-साल 21% की मजबूत वृद्धि परिलक्षित है। कंपनी ने कर के बाद लाभ (पी ए टी) में 42% की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 295.41 करोड़ रुपये से बढ़कर 468.53 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त 2024-25 में, मध्य प्रदेश में कंपनी की प्रमुख इकाई, मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट ने भूमिगत खदानों से 2.73 मिलियन टन तांबे का अयस्क उत्पादित किया है, जो इस खदान से शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक तांबे का अयस्क उत्पादन है।

ईबीआईटीडीए का अंतर वित्त वर्ष 2024-25 में 38% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 34% था, जो 4 गुना की वृद्धि दिखाता है।

जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण और कार्बन कम करने की स्थितियों द्वारा संचालित एनएच ऊर्जा और इलेक्ट्रिक खिंचाव की ओर बढ़ रही है, आने वाले वर्षों में तांबे की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है।

केंदाडीह खनन पट्टे का समझौता औपचारिक रूप से 04.10.2025 को किया गया

तांबा खनन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में, केंदाडीह खनन पट्टे का समझौता औपचारिक रूप से 04.10.2025 को किया गया। यह झारखंड सरकार का खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे देश में खनिज खनिजों के केंद्र के तौर पर झारखंड की स्थिति मजबूत होती है।

राखा माइनिंग लीज डीड पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए

तांबे के खनन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर, राखा माइनिंग लीज डीड को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से पूरा किया गया।

राखा तांबे की खान परियोजना से रोज़गार पैदा होने, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और स्थानीय आर्थिक विकास में काफी मदद मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह तांबे सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, पूर्वी सिंहभूम के जिला आयुक्त ने कहा कि राखा माइनिंग लीज डीड पर अमल, झारखंड सरकार की जिम्मेदार खनन को बढ़ावा देने, पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने और क्षेत्र के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने की उठाने को बरकरार है। श्री सत्यार्थी ने कहा कि यह परियोजना पूर्वी सिंहभूम जिले में समेकित विकास और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह घटनाक्रम झारखंड सरकार द्वारा खनन और संबद्ध उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने पर दिए जा रहे जोर को दर्शाता है जिससे देश में खनिज संपदा के केंद्र के रूप में झारखंड की स्थिति और मजबूत होगी।

केनाडीह माइंस से मोसाबनी कंसंट्रेटर प्लांट तक तांबे के अयस्क का परिवहनneral

केंदडीह माइंस से मोसाबनी कंसंट्रेट प्लांट तक तांबे के अयस्क को भेजने का काम 20.10.2025 से शुरू हो गया। धार्मिक समारोहों के बाद, इस कार्यक्रम को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की झारखंड इकाई इंडियन कॉपर प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक और इकाई प्रमुख श्री श्याम सुंदर सेठी ने महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट)-मैकेनिकल की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर शुरु किया।

सुरदा खदान का खान विकास अनुबंध आर के अर्थ रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया

आईसीसी , एचसीएल की झारखंड स्थित इकाई की सुरदा माइंस का खनन कार्य और विकास का अनुबंध मैसर्स आर के अर्थ रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। 05.02.2025 को, कंपनी ने पिछले ठेकेदार से खनन स्थल का कार्यभार संभाल लिया है।

एचसीएल को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" ग्रेड मिला

हिंदुस्तान कॉपर को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" ग्रेड मिला। 06.02.2025 को कोलकाता में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सीएल) ने समझौता ज्ञापन ग्रिड के अनुसार प्रदर्शन के मामले में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की है। वित्त वर्ष 2019-20 में नुकसान उठाने के बाद, एचसीएल पिछले तीन सालों से लगातार लगभग 400 करोड़ रुपये का कर से पहले मुनाफा कमा रही है। कंपनी को 12 साल बाद डीपीई द्वारा यह ग्रेड दिया गया है।

हिंदुस्तान कॉपर ने महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा पर वैश्विक संगोष्ठी आयोजित की

भारत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है जो हमारे माइक्रोचिप्स, बैटरी, विद्युत यौगिकों को शक्ति देते हैं, स्वच्छ ऊर्जा, संरेखण सिस्टम, सेमीकंडक्टर, संरेखण तकनीक को चलाते हैं। हालांकि, ये ज्यादातर चट्टानों में बंद होते हैं जिनके निष्कर्षण के लिए विशेष खनिज प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। ठोस चट्टानों के खनन में अपनी अद्वितीय विशिष्टताओं के साथ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) उन कुछ कंपनियों में से एक है जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में कदम रखने और हमारे राष्ट्र को मूल्यवान सेवा प्रदान करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। इस विजन के अनुरूप, एच सी एल सीमाओं से परे देख रहा है।

इसी क्रम में, एचसीएल ने अपने 59वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए 9 नवंबर, 2025 को कोलकाता में विकसित भारत @ 2047 के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों, खनन दिग्गजों और प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भारत सरकार के कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने अपने वर्चुअल मुख्य भाषण में देश के लिए खनिज सुरक्षा की मजबूती पर जोर दिया और एचसीएल से इस प्रयास में सार्थक भूमिका निभाने का आग्रह किया। भारत सरकार के कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने वैश्विक उद्यमिता के विशेषज्ञों के विचार-विमर्श और तकनीकी पाठ्यक्रमों से समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को आयोजित करने के लिए एचसीएल की सराहना की।

यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय खनन कंपनियों और उनके विदेशी समकक्षों के बीच सहयोग की संभावनाओं को खोलेगा।

केसीसी खदान में सतह से 400 मीटर नीचे गहराई में व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्थापित किया गया

राजस्थान में एचसीएल की खेतड़ी भूमिगत खदान में सतह से 400 मीटर नीचे गहराई से टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी-डीओटी) के माध्यम से एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्थापित किया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह ने खेतड़ी खदान में 400 मीटर की गहराई पर मौजूद एचसीएल और सी-डीओटी के अधिकारियों से बात की। सी-डीओटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजकुमार उपाध्याय और सी-डीओटी के वैज्ञानिक 'जी' 5जी आरएएन के समन्वयक श्री हरि प्रसाद एस वी भी व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़े थे।

श्री लक्ष्मैया पी के नेतृत्व में सी-डीओटी की सात सदस्यीय टीम खेतड़ी भूमिगत खदान में उपस्थित थी, साथ ही खेतड़ी और प्रधान कार्यालय के एचसीएल सिस्टम और खनन अधिकारी भी इस परियोजना को सफल बनाने में मदद करने के लिए मौजूद थे। भूमिगत खदानों के अंदर इंटरनेट पहुंच प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास के हिस्से के रूप में एक पायलट परियोजना के रूप में एचसीएल ने 5 जी निजी नेटवर्क को सतह पर मौजूदा नेटवर्क के साथ मिला दिया। भूमिगत खदानों के अंदर इंटरनेट पहुंच, बेहतर संचार, सुरक्षा और उत्पादकता के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

एच सी एल ने केसीसी में राजस्व इकट्ठा करने को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल शुरू किया

श्री संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल), ने डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक (ऑपरेशंस) और निदेशक (माइनिंग) - एडिशनल चार्ज, श्री हरसिमरन सिंह, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की उपस्थिति में, एक्सिस बैंक (एचसीएल के कंसोर्टियम बैंकर) की मदद से विकसित एक ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (एच सी एल की राजस्थान इकाई) के लीज-आधारित क्वार्टर और दुकानों से राजस्व इकट्ठा करने को आसान बनाने के लिए है। श्री रवि कुमार गुप्ता, ईडी (वित्त), एचसीएल , श्री जी डी गुप्ता, ईडी और यूनिट हेड, केसीसी , श्री सितेन्दु अंकुर, एजीएम (सिस्टम्स), एचसीएल के अलावा, इस कार्यक्रम में श्री अंकित जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रीजनल हेड, ईस्ट - पीएसयू बिजनेस, एक्सिस बैंक भी मौजूद थे। डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह लेन-देन को आसान, तेज़, सुरक्षित और अनियमित बनाने की दिशा में एक कदम है।

एचसीएल ने डब्ल्यूसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (**डब्ल्यूसीएल**) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (**एचसीएल**) के बीच 03.11.2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) ईकाई , राजस्थान और मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एमसीपीआई) ईकाई , मध्य प्रदेश की भूमिगत खानों को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, नागपुर (एम आर एस नागपुर) से रेस्क्यू कवर और रेस्क्यू संबद्धता प्रदान करने के लिए है।

कोलिहान माइंस रेस्क्यू टीम को सम्मानित किया गया

डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, डायरेक्टर (ऑपरेशन) और डायरेक्टर (माइनिंग) - एडिशनल चार्ज ने 02/04/2025 को खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के सभी रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्तियों (RTP) से मुलाकात

की। उनके साथ श्री घनश्याम दास गुप्ता, ईडी और यूनिट हेड, केसीसी , श्री पुरुषोत्तम दास बोहरा, महाप्रबंधक (माइंस) और केसीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। 14.05.2024 को हुए कोलिहान माइंस दुर्घटना के दौरान किए गए असल बचाव अभियान और बीसीसीएल, धनबाद में 53वीं अखिल भारतीय खनन बचाव प्रतियोगिता में एचसीएल बचाव दल की उपलब्धियों के बारे में श्री जी डी गुप्ता, श्री पुरुषोत्तम दास बोहरा, सुश्री सुजिता विश्वनाथन, विभाग अध्यक्ष केसीसी अस्पताल , श्री अब्दुल तस्लीम आलम, इंचार्ज रेस्क्यू रूम, श्री सुनील कुमार कटेवा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी और आरटीपी श्री शिवलाल सुथार, श्री मोहर सिंह और श्री राम स्वरूप लेघा ने जानकारी दी। यह माइंस सुरक्षा और बचाव अभियानों के महत्व पर जोर देने के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था।

कोलिहान माइंस दुर्घटना और 53वीं अखिल भारतीय खनन बचाव प्रतियोगिता में टीम की उपलब्धियां चर्चा का मुख्य विषय थे। डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के सतत प्रयासों को स्वीकार किया और 53वीं अखिल भारतीय खनन बचाव प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर अपनी प्रशंसा व्यक्ति की।

केसीसी में उनका दौरा और बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ बैठक ने टीम का मनोबल और बढ़ाया है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा।

खेतड़ी और कोलिहान खदान को पुरस्कार

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की कोलिहान और खेतड़ी बचाव टीमों द्वारा राजस्थान में 11 से 13 अक्टूबर तक रामपुरा अगुचा माइंस, हजडल में आयोजित 11वीं इंटर जोनल बचाव प्रतियोगिता - 2025 में जीते गए पुरस्कार। 1. कोलिहान टीम को रेस्क्यू रिले में पहला स्थान 2. FAB में दूसरा स्थान हासिल हुआ। कोलिहान टीम को समग्र रूप से तीसरा स्थान, खेतरी टीम को बचाव एवं पुनर्प्राप्ति में चौथा स्थान मिला। खेतरी टीम के ऋषि यादव को सर्वश्रेष्ठ सदस्य का पुरस्कार मिला।

एम सी पी बचाव दल को पुरस्कार

मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यूनिट, मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (**एम सी पी**) की बचाव टीम ने टर्नआउट ड्रिल इवेंट में दूसरा पुरस्कार हासिल किया। बचाव टीम ने डीजेएमएस की देखरेख में एमओआईएल द्वारा 12 से 15 अक्टूबर 2025 तक मानसर माइंस में आयोजित 54वीं जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता में उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन और टीम वर्क का प्रदर्शन किया।

एम सी पी माइन्स के लिए पुरस्कार

एम सी पी माइंस ने दूसरे मेटालिफेरस माइंस सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन 2024 में निम्नलिखित पुरस्कार जीते: 1. ओवरऑल - पहला 2. विस्फोटक का भंडारण, परिवहन और उपयोग - पहला 3. प्लांट और एयर कंडीशनिंग - पहला 4. इलेक्ट्रिकल उपकरण और स्थापना- पहला। डीजीएमएस परासिया क्षेत्र की देखरेख में अंतिम दिन का कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह 14.02.25 को छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था।

आई सी सी ईकाई की केंदाडीह कॉपर माइन्स के लिए पुरस्कार

महानिदेशालय खान सुरक्षा, चाईबासा क्षेत्र, चाईबासा की देखरेख में 62वें वार्षिक मेटालिफेरस माइंस सुरक्षा सप्ताह सेलिब्रेशन 2024-25 में, झारखंड में **एचसीएल** की इकाई भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स की केंदाडीह कॉपर माइंस ने अलग-अलग श्रेणियों में चार पुरस्कार (ग्रुप- A3-B) जीते हैं: पहला पुरस्कार - वाइंडिंग/भूमिगत फ्लाइंग, फाइनेंस, प्लांट और उपकरण रखरखाव दूसरा पुरस्कार वीटीसी प्रशिक्षण सुविधाओं/प्राथमिक उपचार में दूसरा पुरस्कार वैधानिक जनशक्ति, प्रावधान और रिकॉर्ड (विभागीय) में दूसरा पुरस्कार, अग्निशमन, आपातकालीन तैयारी, मॉक ड्रिल में द्वितीय पुरस्कार

इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की सुरा और केंदाडीह माइंस को पुरस्कार-

31वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह, रांची क्षेत्र में, झारखंड में **एचसीएल** की ईकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की सुरा और केंदाडीह माइंस ने निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं। सुरा माइन: 1. ओवरऑल पहला पुरस्कार विजेता 2. विजेता: व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास 3. विजेता: खनिज संरक्षण 4. विजेता: वेस्ट डंप प्रबंधन 5. विजेता: प्रचार और प्रसार केंदाडीह माइन: 6. विजेता: सतत विकास

एमसीपीआई में 132 केवी सब स्टेशन का विस्तार-

मालंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, एचसीएल की मध्य प्रदेश स्थित यूनिट में ईडी और इकाई प्रमुख, श्री नागेश शेनॉय द्वारा 132 केवी सब स्टेशन के विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया गया।

श्री आर आर मिश्रा, खान सुरक्षा निदेशक, डीजेएमएस, चाईबासा क्षेत्र और चाईबासा क्षेत्र और रांची जोन के अन्य डीजेएमएस अधिकारियों, श्री श्याम सुंदर सेठी, कार्यकारी निदेशक और इकाई प्रमुख (आई सी सी) और श्री दीपक श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (परियोजनाएं), आई सी सी की गरिमामयी उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए गए।

खेतड़ी तांबे की खान को पुरस्कार

एचसीएल की राजस्थान स्थित खेतड़ी कॉपर खदान ने 35वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह 2024-25 के अंतिम दिन 27 अप्रैल 2025 को अजमेर में आईबीएम, अजमेर क्षेत्र के तत्वावधान में आयोजित समारोह में पूरी तरह से मशीनीकृत खान (भूमिगत) श्रेणी में समग्र प्रदर्शन में तीसरा पुरस्कार जीता, साथ ही निम्नलिखित तीन पुरस्कार भी जीते: (1) खनिज संवर्धन- दूसरा पुरस्कार (2) वेस्ट डंप प्रबंधन- दूसरा पुरस्कार (3) सतत विकास- तीसरा पुरस्कार

एचसीएल की कोलिहान कॉपर माइन ने भी निम्नलिखित पुरस्कार जीते:- (1) पर्यावरण निगरानी- पहला पुरस्कार (2) वेस्ट डंप प्रबंधन- तीसरा पुरस्कार कार्यक्रम में श्री जी डी गुप्ता, कार्यकारी निदेशक और यूनिट हेड/केसीसी , श्री मनीष गवई, डीजेएम (सिविल) और पर्यावरण, श्री नागेश राजपुरोहित, मुख्य प्रबंधक (अन्वेषण), श्री संजय कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (खान) और श्री नरेंद्र प्रुसेठ, प्रबंधक (खान) उपस्थित थे।

29 केंद्रीय श्रम कानूनों का 4 कोड में एकीकरण

सरकार ने एक सरल, अधिक आधुनिक और श्रमिक-सख्त ढांचा बनाने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कोड में एकीकृत किया है। यह बदलाव हर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने, वेतन कानूनों को सरल बनाने और नौकरियों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई मलांजखंड कॉपर परियोजना (एम सी पी) के सभी कर्मचारियों को श्री नागेश शेनॉय, ईडी और ईकाई प्रमुख, एमसीपीआई के निरीक्षक के अनुसार और श्री डी आर पाटिल, यूनियन अध्यक्ष द्वारा सूचना पत्र और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन नए श्रम कोड के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया।

एमसीपी में कन्वेंशनल थिकनर फिर से शुरू हुआ

मरम्मत और रखरखाव के बाद **एमसीपी** कंसंट्रेटर प्लांट में कन्वेंशनल थिकनर शुरू हो गया है। एमसीपी यूनिट हेड, श्री नागेश शेनॉय ने दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए पूजा की।

केसीसी ईकाई को 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया

खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (**केसीसी**), राजस्थान में एचसीएल की यूनिट को माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा 07.07.2025 को जयपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के लिए 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। टीम एचसीएल (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड) का नेतृत्व श्री संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एचसीएल, डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक (संचालन) और निदेशक (खनन) - अतिरिक्त प्रभार, श्री जी डी गुप्ता, ईडी और यूनिट प्रमुख, केसीसी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

एमसीपीआई को 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया

मलांजखंड तांबे प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में एचसीएल की एकाई को माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा 07.07.2025 को जयपुर में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के लिए 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। टीम एच सी एल(हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड) का नेतृत्व एचसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह, डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक (संचालन) और निदेशक (खनन) - अतिरिक्त प्रभार, श्री नागेश शेनॉय, ईडी और यूनिट प्रमुख, एमसीपी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

एचसीएल ने ई-कार्यालय शुरू किया

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 07.10.2025 को ई-ऑफिस लॉन्च किया, जो डिजिटल गवर्नेंस और पेपरलेस कामकाज की दिशा में एक कदम आगे है। श्री संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (**एचसीएल**) ने डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक (संचालन) और निदेशक (खनन) - अतिरिक्त प्रभार, **एचसीएल** , श्री आर वी एन विश्वेश्वर, निदेशक (वित्त), एच सी एल , श्री हरसिमरन सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी, **एचसीएल** और **एचसीएल** कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई-कार्यालय का उद्घाटन किया।

एचसीएल इकाइयों और कार्यालयों के यूनिट प्रमुख और ई-ऑफिस के मुख्य सदस्य, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के ई-ऑफिस की टीम, भारत भर में कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल (सीएससी एसपीवी) डेटा सेंटर की क्लाउड सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुईं।

ई-कार्यालय लागू होने से डिजिटल, पेपरलेस साक्षरता के माध्यम से ज़्यादा सेवाएँ, जवाबदेही और दक्षता प्रदान करके ऑफिस के काम में सुधार होगा। मुख्य लाभों में तेज़ी से निर्णय लेना, सुनिश्चित डेटा सुरक्षा, बेहतर सहयोग, साक्षरता की शारीरिक कमजोरी में कमी और कार्य संस्कृति में ज़्यादा सकारात्मक बदलाव शामिल हैं।

बीआईएस का एचसीएल के साथ संगठन-

भारतीय मानक ब्यूरो को एचसीएल के साथ आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित लाइसेंसधारी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त है और उसने एचसीएल को उनके 78वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है।

आईसीसी में डोना पत्ता के उत्पादन के लिए मशीनों और सामग्री का वितरण

13/03/2025 को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ईकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 के लिए, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुसाबनी ब्लॉक के 6 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच डोना पत्ता और मुढ़ी के उत्पादन के लिए मशीनरी और सामग्री का वितरण कार्यकारी निदेशक सह यूनिट हेड श्री श्याम सुंदर सेठी द्वारा किया गया।

कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में डीएमएफ प्रदर्शनी में एचसीएल का स्टॉल

श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार, सुश्री फरीदा एम. नाइक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार। भारत के श्री संजीव कुमार सिंह, विभागीय और प्रबंध निदेशक, **एचसीएल** और टीम **एचसीएल** , कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में डीएमएफ प्रदर्शनी में **एचसीएल** स्टॉल पर मौजूद थे। **एचसीएल** के अलावा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा स्वयं सहायता समूहों (**एचसीएल** द्वारा समर्थित) के उत्पाद जैसे डोकरा कलाकृतियाँ, लकड़ी के हस्तशिल्प, जूट के बैग, ताज़ा पिसा मसाला, खाने-पीने की चीज़ें, आदि बिक्री के लिए रखे गए थे।

भारत पर्व 2025 में एचसीएल

भारत पर्व 2025 के उद्घाटन दिवस पर, खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती फरीदा एम. नाइक ने मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। यह पवेलियन भारत की समृद्ध खनिज विरासत और जीएसआई, एचसीएल, एमईसीएल और नालको के योगदान को दर्शाता है। श्रीमती नाइक ने राष्ट्र निर्माण में खनन के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियों को उजागर करने में अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

जीएसआई परिसर में एचसीएल का बूथ

माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी का कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की 175वीं भूवैज्ञानिक विरासत के अवसर पर एचसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह और एचसीएल के वित्त निदेशक श्री घनश्याम शर्मा ने हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर एचसीएल ने जीएसआई परिसर में एक स्टॉल लगाया था।

खनन इंडबा 2025 में एच सी एल

दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त श्री प्रभात कुमार ने 3 फरवरी, 2025 को केप टाउन में आयोजित माइनिंग इंडाबा 2025 में एचसीएल के इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विवेक कुमार बाजपेयी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

पशु मेले में एचसीएल का पवेलियन:

बिहार के सारण जिले के हरिहर क्षेत्र में आयोजित विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले में खान मंत्रालय के पवेलियन में 23.11.2025 को भारत सरकार के कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे को खान मंत्रालय की हालिया उपलब्धियों, सामाजिक कल्याण के लिए अपनाई गई योजनाओं और पहलों तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी विशाल भूमिका के बारे में जानकारी दी । खान मंत्रालय का पवेलियन सोनपुर मेले में देश के खनिज संसाधनों और खनन क्षेत्र में सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक है। यह जन भागीदारी को मजबूत करता है, विश्वास का निर्माण करता है और समावेशी विकास में इस क्षेत्र की भूमिका को उजागर करता है।

एचसीएल ने आर के एचआईवी एंड एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के साथ एक समझौता पत्र पर

हस्ताक्षर किया।

कॉर्पोरेट सीएसआर पॉलिसी के अंतर्गत 'स्वास्थ्य' के लिए एक सीएसआर पहल के रूप में, एक मेगा मेडिकल कैंप आयोजित करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और आर के एचआईवी एंड एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर के दौरान एचसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह, एचसीएल के निदेशक (वित्त) श्री घनश्याम शर्मा, निदेशक (संचालन) श्री संजीव कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एमसीपी में नई ऑक्सीजन पाइपलाइन का उद्घाटन

मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में कार्यकारी निदेशक, एमसीपी श्री नागेश शेनॉय ने एक नई ऑक्सीजन पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पहल हमारे कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इस अपग्रेड के साथ, एचसीएल सभी के लिए सुलभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाता है।

एचसीएल ने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची के बीच 21.03.2025 को शैक्षणिक-उद्योग तालमेल, सहयोगात्मक विकास, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, एचसीएल ज्ञान-साझाकरण, कौशल वृद्धि और सतत विकास की शक्ति को महत्व देता है। साझेदारी की शक्ति के प्रमाण के रूप में, यह समझौता ज्ञापन कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, उद्योग-शिक्षा सहयोग और क्षमता-निर्माण पहलों के प्रति एचसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आईसीसी यूनिट में एसओपी डायरी का शुभारंभ

सुरदा कॉपर माइन के सुरक्षा विभाग ने ईडी और यूनिट हेड, आईसीसी आईसीसी श्री एस एस सेठी के नेतृत्व में 01.04.2025 को सफलतापूर्वक एक पॉकेट एसओपी डायरी का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य खदान में सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाना है। लॉन्च के बाद, पॉकेट एसओपी डायरी पर्यवेक्षकों, ऑपरेटरों और अन्य खनन कर्मियों को वितरित की गई, जिससे आवश्यक सुरक्षा प्रक्रियाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हुई। इस कदम से कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करने और परिचालन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

एचसीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए वार्षिक योजना बैठक का आयोजन किया।

वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए वार्षिक योजना बैठक, एक दो दिवसीय विचार-विमर्श कार्यशाला, 2-3 मई, 2025 को एचसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें एचसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह और निदेशक श्री घनश्याम शर्मा उपस्थित रहेंगे। निदेशक वित्त विभाग के प्रमुख डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, संचालन निदेशक और खनन निदेशक - अतिरिक्त प्रभार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हरसिमरन सिंह, इकाई प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। एचसीएल की देशभर की इकाइयों के सभी प्रमुख अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे। बैठक का उद्देश्य एचसीएल की गतिविधियों और पहलों को कंपनी के विजन के अनुरूप रणनीतिक रूप से संरेखित करना था। 1967 से राष्ट्र की सेवा में कार्यरत, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे के सतत खनन के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।

एचसीएल और राइट्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन-

खान मंत्रालय द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में, आयोजित क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग सेमिनार के दौरान श्री संजीव कुमार सिंह, सीएमडी, एचसीएल, और श्री राहुल मिथल, सीएमडी, राइट्स लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों सहित धातुओं और खनिजों की तीव्र, विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी भारत और विदेशों में संयुक्त अन्वेषण, निष्कर्षण, शोधन और उत्पादन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो उपरोक्त समझौता ज्ञापन में उल्लिखित रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी पूरक तकनीकी और वित्तीय ताकत का लाभ उठाएगी।

एचसीएल ने सीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने खनिज लाभकारी, प्रौद्योगिकी साझाकरण, ज्ञान विनिमय और अन्य मूल्य वर्धित गतिविधियों के अलावा भारत और विदेशों में तांबे और महत्वपूर्ण खनिज भंडार की खोज और दोहन पर सहयोग करने के लिए 30.06.2025 को कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एचसीएल ने "साइबर स्वच्छता और सुरक्षा" पर कार्यशाला का आयोजन किया

डिजिटल इंडिया के 10 साल होने पर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने कोलकाता में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में "साइबर स्वच्छता और सुरक्षा" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें नागरिकों और प्रणालियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करने और एक सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए देश भर

की सभी इकाइयों और कार्यालयों ने भाग लिया, क्योंकि भारत के डिजिटल परिदृश्य का विस्तार हो रहा है।

एचसीएल के सीवीओ ने पूर्वी भारत के संगठनों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया

18 जुलाई, 2025 को कोलकाता में पूर्वी भारत के केंद्रीय संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण और संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय सीवीसी और वीसी के साथ-साथ सचिव, सीटीई, जेएस और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार भी उपस्थित थे।

एचसीएल ने केसीसी में राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान पोर्टल शुभारंभ किया।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह ने निदेशक (संचालन) डॉ. संजीव कुमार सिन्हा और निदेशक (खनन) - अतिरिक्त प्रभार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हरसिमरन सिंह की उपस्थिति में एक्सिस बैंक (एचसीएल के एक कंसोर्टियम बैंकर) के सहयोग से विकसित एक ऑनलाइन भुगतान पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स (राजस्थान में एचसीएल की इकाई) के पट्टे पर दिए गए क्वार्टरों और दुकानों से राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। एचसीएल के वित्त विभागाध्यक्ष श्री रवि कुमार गुप्ता, केसीसी के वित्त विभागाध्यक्ष और यूनिट हेड श्री जी डी गुप्ता, एचसीएल के एजीएम (सिस्टम्स) श्री सीतांदु डैश के अलावा, एक्सिस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्वी क्षेत्र के पीएसयू बिजनेस हेड श्री अंकित जैन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप, यह लेनदेन को आसान, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम है।

एचसीएल को सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ-

श्री घनश्याम शर्मा, निदेशक (वित्त), एचसीएल, को सीआईएल द्वारा ताज ताल कुटीर, कोलकाता में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2024 में पूर्वी भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए सीएसआर में लगातार योगदान हेतु "सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार" मिला।

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की राष्ट्रीय संगोष्ठी

श्री संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एचसीएल, ने 22-01-2025 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति (उपक्रम), कोलकाता की समीक्षा बैठक सह राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इसमें कोलकाता में स्थित लगभग सभी केंद्र सरकार के उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को सक्रिय सहयोग के लिए भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

व्यवस्थित सहायता नियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्य प्रदेश में एचसीएल की इकाई मलांजखंड कॉपर परियोजना के प्रशिक्षण केंद्र में 08.01.2025 को व्यवस्थित सहायता नियम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 47 बॉटमलाइन वैधानिक पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन श्री आशीष डहरवाल, सुरक्षा अधिकारी ने किया।

सीएमडी, एचसीएल, ईएमबीटी 2025 में

सीएसआईआर-एनएमएल द्वारा 23 जुलाई 2025 को जमशेदपुर में आयोजित खनिज लाभकारी प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान (ईएमबीटी) 2025 के उद्घाटन समारोह में, श्री संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) ने ईडी और इकाई प्रमुख, आई सी सी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने खनिज लाभकारी प्रौद्योगिकियों में नवाचार और सहयोग के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया।

हिंदुस्तान कॉपर और नॉर्मेट ग्लोबल बोर्ड के बीच रणनीतिक बैठक

अपनी भारत यात्रा के हिस्से के रूप में, नॉर्मेट ग्रुप ओवाई बोर्ड ने 05.09.2025 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह के साथ एक रणनीतिक बातचीत की। प्रतिष्ठित नॉर्मेट ग्रुप बोर्ड के सदस्यों और सीएमडी, एचसीएल के बीच रणनीतिक चर्चाओं ने नॉर्मेट और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच तालमेल और साझा दृष्टिकोण को दर्शाया। हिंदुस्तान कॉपर के साहसिक विस्तार दृष्टिकोण और नॉर्मेट की भूमिगत विशेषज्ञता के साथ, बैठक ने एक उच्च-प्रभाव वाली साझेदारी के लिए मंच तैयार किया। नॉर्मेट और एचसीएल मिलकर स्मार्ट, भविष्य के लिए तैयार समाधान के ज़रिए नवाचार को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना और भारत की खनन की महत्वाकांक्षाओं को सहायता देना चाहते हैं। नॉर्मेट ग्रुप बोर्ड, जिसके लीडर नॉर्मेट के ग्लोबल सीईओ मिस्टर आरो कैंटेल, नॉर्मेट इंडिया और एमई के एमडी मिस्टर एड सैंटामारिया, मिस्टर सुभासिस मोहंती और एचसीएल के चेयरमैन मिस्टर संजीव सिंह थे, उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान और दिलचस्प सवाल-जवाब देखना प्रेरणादायक था। एआई-संचालित युग में तांबे की मांग बढ़ने के साथ, गहरे खनन ही एकमात्र संभव समाधान के रूप में सामने आती है - जो अपने साथ बड़ी चुनौतियाँ भी लाती है। सुरक्षा, उत्पादकता और लागत प्रभावी उत्पादन सुनिश्चित करना नवाचार, स्वयं संचालित और भविष्य के लिए तैयार उच्चस्तरीय खनन पर निर्भर करेगा, जहाँ नॉर्मेट हिंदुस्तान कॉपर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहयोगी परियोजनाओं के ज़रिए, नॉर्मेट हिंदुस्तान कॉपर को उसके दृष्टिकोण को साकार करने और उसकी महत्वाकांक्षी दो-चरणों वाली उत्पादन विस्तार योजनाओं के लिए रास्ता बनाने में मदद करेगा।

एचसीएल कॉर्पोरेट कार्यालय में 5एस प्रणाली पर कार्यक्रम का आयोजन

21 मार्च, 2025 को एचसीएल में **5एस** प्रणाली पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एचसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह, वित्त निदेशक श्री घनश्याम शर्मा, संचालन निदेशक श्री संजीव कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सत्र का संचालन अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) और राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य और एनएसएचएम नॉलेज कैंपस के प्रोफेसर डॉ. अमित चकलेदार ने किया। इस सत्र में एचसीएल की सभी इकाइयों और कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

एचसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

28.02.2025 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में परियोजना प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एचसीएल के निदेशक (वित्त) श्री घनश्याम शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। सत्र का संचालन श्री अनिर्बन दत्ता, संस्थापक और सीईओ, पिमेकास इंजीनियरिंग

सॉल्यूशंस, मान्यता प्राप्त चार्टर्ड इंजीनियर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के कॉर्पोरेट सदस्य और आईएसटीडी के सदस्य द्वारा किया गया। इसमें एचसीएल की सभी इकाइयों और कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

एचसीएल ने सीआईएल के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने 30.06.2025 को कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और विदेश में तांबे और महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की खोज और दोहन के साथ-साथ खनिज प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, ज्ञान के आदान-प्रदान और अन्य मूल्य वर्धित गतिविधियों पर सहयोग करने के लिए किया गया है। एमओयू पर सीआईएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री पी एम प्रसाद, एचसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार श्री संजीव कुमार सिंह, सीआईएल के निदेशक (विपणन) और निदेशक (व्यवसाय) श्री मुकेश चौधरी, और एचसीएल के निदेशक (संचालन) और निदेशक (खनन) - अतिरिक्त प्रभार डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, और एचसीएल और सीआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

सीआईएल ने "साइबर स्वच्छता और सुरक्षा" पर कार्यशाला का आयोजन किया

जैसे ही डिजिटल इंडिया 10 साल का हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (**सीआईएल**) ने कोलकाता में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में "साइबर स्वच्छता और सुरक्षा" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश भर की सभी इकाइयों और कार्यालयों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य नागरिकों और प्रणालियों को साइबर खतरों से बचाने और भारत के डिजिटल परिदृश्य के विस्तार के साथ एक सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर देना था।

हैदराबाद में कॉपर विजन दस्तावेज़ का अनावरण किया

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में सतत और जिम्मेदार खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉपर विजन दस्तावेज़ का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री वी. एल. कांता राव, सचिव (खान), श्रीमती रूपिंदर बरार, अतिरिक्त सचिव (कोयला), श्री विवेक कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव (खान), श्री पी. एम. प्रसाद, सीएमडी, सीसीआईएल, श्री संजीव कुमार सिंह (सीएमडी, एचसीएल) और प्रमुख हितधारक भी उपस्थित थे। खान मंत्रालय की ओर से एचसीएल द्वारा सुगम बनाए गए इस दस्तावेज़ में घरेलू तांबा उद्योग के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है, जो वैश्विक रुझानों के अनुरूप है और तांबा धातु और खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की रणनीतियों पर प्रकाश डालता है।

केसीसी इकाई में रॉक मैकेनिक्स विषय पर तकनीकी सत्र

12.07.2025 को राजस्थान में एचसीएल की ईकाई खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) में 'स्टॉप माइनिंग, रूफ सपोर्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन में स्ट्रेटा कंट्रोल के लिए रॉक मैकेनिक्स' विषय पर एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर डॉ. देबासिस देब ने केसीसी प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। इसमें श्री पी डी बोहरा, जीएम (माइंस), श्री बी साहू, एजीएम (माइंस) के साथ-साथ इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरों ने हिस्सा लिया।

समापन सेशन के दौरान श्री जी डी गुप्ता, ईडी और इकाई प्रमुख, केसीसी ने अपने समापन भाषण में खनन अभियंता की भूमिका पर ज़ोर दिया, जो सुरक्षित भूमिगत खनन के लिए महत्वपूर्ण है।

I. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)

अवलोकन

एमईसीएल का दृष्टिकोण है "देश और उससे आगे मिनरल एक्सप्लोरर बनना।"

मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (**एमईसीएल**), खान मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न-I सीपीएसई, भारत की सबसे प्रमुख खनन अन्वेषण एजेंसी है, जो पूरी खनन मूल्य चेन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाधान प्रदान करती है। क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के अलावा, **एमईसीएल** के अलावा खनिज खण्ड की नीलामी का समर्थन करने के लिए उन्नत भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, कोर ड्रिलिंग, संसाधन मूल्यांकन, तकनीकी परामर्श, और भू-रासायनिक और भूभौतिकीय विश्लेषण प्रदान करता है। ऊर्जा खनिजों, लौह और अलौह धातुओं, औद्योगिक और उर्वरक खनिजों, कीमती और दुर्लभ खनिजों, साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, एमईसीएल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो भारत में नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता और स्थायी खनिज विकास को बढ़ावा देता है।

एमईसीएल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक अन्वेषण रणनीतियों के माध्यम से ईवी बैटरी खनिजों, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई), ग्रेफाइट और पीजीई जैसे उभरते क्षेत्रों का समर्थन करने में भी सबसे आगे है। अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान, उन्नत उपकरणों और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, **एमईसीएल** सरकारी एजेंसियों, पीएसयू और औद्योगिक हितधारकों को अनुकूलित, उच्च-सटीक और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। निम्नलिखित अनुभाग 30 नवंबर 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमईसीएल की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदर्शन

1. **अन्वेषण गतिविधियाँ और प्रदर्शन**
   नवंबर, 2025 तक, एमईसीएल ने 2,78,436 मीटर की खोजपूर्ण ड्रिलिंग हासिल की, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई 2,68,235 मीटर ड्रिलिंग की तुलना में 3.80% की वृद्धि है। इस अन्वेषण में ऊर्जा खनिज, लौह और अलौह धातु, औद्योगिक और उर्वरक खनिज, कीमती और दुर्लभ खनिज, साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों सहित खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जो भारत की खनिज सूची में एमईसीएल के व्यापक योगदान को दर्शाता है, विशेष रूप से रणनीतिक और उच्च मांग वाले खनिजों के लिए।

2. **वित्तीय प्रदर्शन और राजस्व वृद्धि**
   अप्रैल से नवंबर 2024 की अवधि में, एमईसीएल ने कुल ₹234.06 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। कंपनी ने ₹37.39 करोड़ का महत्वपूर्ण कुल लाभ भी हासिल किया, जो पिछले वित्तीय सालों की इसी अवधि की तुलना में 13.08% ज़्यादा है।

3. **भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और राष्ट्रीय खनिज सूची**

एमईसीएल राष्ट्रीय खनिज सूची को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवंबर, 2025 तक, कंपनी ने 29 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें एनएमईटी के लिए 15, संविदात्मक 2, ऊर्जा खनिजों के लिए 9 और एनजीपीएम के तहत भूभौतिकीय जांच के लिए 3 शामिल हैं। इन योगदानों ने राष्ट्रीय सूची में बहुमूल्य संसाधन जोड़े हैं।

4. **परियोजना स्वीकृतियां और चल रहे कार्य**

नवंबर, 2025 तक, एमईसीएल ने एनएमईटी से 14 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों सहित कुल ₹72.69 करोड़ की 23 परियोजना स्वीकृतियां सफलतापूर्वक हासिल कर ली हैं। वर्तमान में 54 ब्लॉकों में क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण गतिविधियाँ प्रगति पर हैं, जिनमें 20 वस्तुओं को कवर करने वाले 33 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक और जी-3 और जी-4 स्तर के खोजपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 13 राज्य शामिल हैं।

5. **क्षमता वृद्धि:**

एमईसीएल ने अत्याधुनिक एलआईबीएस कोर स्कैनर को शामिल करके अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, जिससे इसकी उन्नत कोर-स्कैनिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कंपनी ने दुर्लभ धातु और आरईई अन्वेषण के लिए गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, एक आधुनिक बोरहोल भूभौतिकीय लॉगिंग प्रणाली और 120 इलेक्ट्रोड से सुसज्जित मल्टी-इलेक्ट्रोड प्रतिरोधकता इमेजिंग सिस्टम के साथ अपनी भूभौतिकीय क्षमता को और उन्नत किया। एमईसीएल ने अपने विनिर्माण केंद्र और रासायनिक प्रयोगशालाओं को उन्नत मशीनरी के साथ बढ़ाया, जिससे अन्वेषण परियोजनाओं के लिए उच्च परिशुद्धता, इन-हाउस विश्लेषणात्मक और निर्माण सहायता प्रदान करने की इसकी क्षमता मजबूत हुई।

6. **खनिज ब्लॉक नीलामी परामर्श-**

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, एमईसीएल ने महत्वपूर्ण खनिज नीलामी के छह चरणों के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान किया। 23 ब्लॉकों के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान किए गए, जिनमें से सभी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके अलावा, एमईसीएल ने चूना पत्थर ब्लॉकों की पहली नीलामी के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को तकनीकी परामर्श प्रदान किया। सात चूना पत्थर ब्लॉकों के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान किए गए, जिनमें से सभी को सफलतापूर्वक शुरू किया गया।

7. **आवश्यक खोज की पहल:**

एमईसीएल ने साल के दौरान कई रणनीतिक खोज कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) की खोज शुरू करना भी शामिल है जिससे भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को मज़बूती मिली है। कंपनी ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, में निचाहोम खंड में लिग्नाइट की खोज भी शुरू की-जो इस क्षेत्र के ऊर्जा विविधीकरण प्रयासों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, एमईसीएल ने राजस्थान के बीकानेर में उर्वरक खनिजों की खोज शुरू की, जिससे कृषि संसाधन सुरक्षा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में और योगदान मिला।

8. **गुणवत्ता प्रमाणन:**

एमईसीएल ने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईएसओ 14001:2015, और कार्य के दौरान स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001:2018 जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन हासिल करके अपनी संस्थागत उत्कृष्टता को मजबूत किया। ये प्रमाणन गुणवत्ता-संचालित संचालन, पर्यावरणीय प्रबंधन और

सभी अन्वेषण और सहायक गतिविधियों में एक सुरक्षित और अनुपालन वाले कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के प्रति एमईसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एमईसीएल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच का समर्थन करने और वैश्विक भू-वैज्ञानिक साझेदारियों को गहरा करने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव रणनीति को और आगे बढ़ाया। कंपनी ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखी, प्राथमिकता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी खनिज मूल्यांकन, परियोजना आकलन और ड्यू-डिलिजेंस अध्ययनों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान दिया। एमईसीएल ने लिथियम और अन्य रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए मौजूदा समझौता ज्ञापन के तहत अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की सरकार के साथ चल रहे सहयोग का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सहयोग से, एमईसीएल ने ज़ाम्बिया में भूवैज्ञानिक मानचित्रण के लिए संयुक्त क्षेत्र जांच की, जिससे अफ्रीका में भारत की भूवैज्ञानिक उपस्थिति का विस्तार हुआ और ज्ञान के आदान-प्रदान और संसाधन विकास के लिए दीर्घकालिक अवसरों को बढ़ावा मिला।

10. **व्यवसाय विकास और वाणिज्यिक साझेदारियाँ**

अपनी व्यवसाय विकास पहलों के माध्यम से, एमईसीएल ने भारत के खनिज क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार और रणनीतिक सहयोग का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। उन्नत अन्वेषण प्रौद्योगिकियों को प्रतिस्पर्धी तकनीकी-वाणिज्यिक समाधानों के साथ एकीकृत करके, कंपनी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों दोनों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। 31 अक्टूबर 2025 तक, एमईसीएल का कार्य पोर्टफोलियो ₹564.24 करोड़ के अनंतिम मूल्य पर है, जिसमें सरकारी संगठन, राज्य डीजीएम/डीएमजी सीपीएसई, और निजी अन्वेषण और खनन कंपनियों सहित प्रमुख ग्राहकों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। एमईसीएल का रणनीतिक जुड़ाव ढांचा ओएमईसीएल, सीएमपीडीआईएल, डीएमजी गोवा, डीजीएम मध्य प्रदेश और एमपीएसएमसीएल, डीजीएम असम के साथ आरआईटीईएस लिमिटेड एचसीएल और एनएमडीसी के साथ चल रहे समझौता ज्ञापन के एक मजबूत नेटवर्क द्वारा समर्थित है। अपने सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करते हुए, एमईसीएल ने खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का की प्रांतीय सरकार के साथ नए समझौता ज्ञापन और समझौते किए; महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ; गुरुत्वाकर्ष और चुंबकीय सर्वेक्षण तथा संबंधित रिपोर्टिंग के लिए जीएसआई (एनआर, सीआर और ईआर), अतिरिक्त अन्वेषण सहायता के लिए एक पूरक ढांचे के माध्यम से एनएलसीआईएल; खनन और अन्वेषण में तकनीकी सहयोग के लिए आईआईटी बॉम्बे; भू-रासायनिक विश्लेषण और गुणवत्ता प्रबंधन पर एसओपी के विकास के लिए आईबीएम; खनन और खनिज क्षेत्र में सहयोग के लिए मेकॉन लिमिटेड; और कोयले और अन्य खनिज संसाधनों के लाभकारी और प्रसंस्करण के लिए सीएसआईआर-एनएमएल। साथ में, ये साझेदारियाँ राष्ट्रीय और वैश्विक खनिज विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में एमईसीएल के बढ़ते प्रभाव और मजबूत भूमिका को दर्शाती हैं।

11. **रणनीतिक विविधीकरण और परामर्श सेवाएं**

एमईसीएल ने विविध तकनीकी, विश्लेषणात्मक और सलाहकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने सेवा पोर्टफोलियो को व्यापक बनाना जारी रखा, एक बहु-विषयक भूवैज्ञानिक संगठन के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ अपने दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन के तहत, एमईसीएल भविष्य की खोज और संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत भू-रासायनिक डेटा उत्पन्न करने के लिए एनजीपीएम सर्वेक्षण कर रहा है। कंपनी ने आगामी महत्वपूर्ण खनिज नीलामियों की तैयारी और कार्यान्वियन में सरकार को व्यापक सहायता प्रदान की, जबकि विभिन्न राज्य डीएमजी को उनके खनिज नीलामी ढांचे को मजबूत करने में तकनीकी सहायता प्रदान की। डब्ल्यूसीएल की ओपनकास्ट कोयला खदान में दोष चित्रण के लिए जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से एमईसीएल की भूभौतिकीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।

क्यूसीआई-मान्यता प्राप्त रेफरी प्रयोगशाला के रूप में, एमईसीएल विश्लेषणात्मक और गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं में अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए, सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए रासायनिक विश्लेषण कर रहा है।

कंपनी ने अन्य अन्वेषण सार्वजनिक उपक्रमों को रिग-मरम्मत सहायता प्रदान करके, अन्वेषण कंपनियों के लिए भूभौतिकीय लॉगर्स की मरम्मत और अंशांकन सहित विशेष उपकरण सेवाएं प्रदान करके और विभिन्न एजेंसियों को ड्रिलिंग सहायक उपकरण की आपूर्ति करके अपनी इंजीनियरिंग और उपकरण सेवाओं का विस्तार किया, जिससे अन्वेषण उद्योग में परिचालन दक्षता मजबूत हुई।

12. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल

एमईसीएल ने अपने परियोजना क्षेत्रों के आसपास के समुदायों के कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है, और ऐसे **सीएसआर** पहल लागू किए हैं जो सतत् विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, ₹106.74 लाख के खर्च के साथ, कंपनी ने छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में पोर्टेबल वॉटर प्यूरिफिकेशन यूनिट, व्हीलचेयर और स्वास्थ्य और शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार, कमजोर समूहों का समर्थन करने और शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी क्रम में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एमईसीएल ने ₹160.50 लाख के आवंटन के साथ अपने **सीएसआर** प्रयासों को बढ़ाया, जिसमें 30 पोर्टेबल वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की स्थापना, सरकारी अस्पतालों को 55 व्हीलचेयर का वितरण, छत्तीसगढ़ में 3 ईसीजी मशीनों की खरीद, और स्वास्थ्य वृक्ष फाउंडेशन द्वारा मुफ्त सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान, बाल शल्य क्रिया मिशन के तहत बाल चिकित्सा सर्जिकल देखभाल और थैलीसीमिया एवं सिकल सेल सोसायटी नागपुर द्वारा छात्रों के लिए एचपीसीअल परीक्षणों जैसे सामाजिक रूप से प्रभावशाली कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। ये लगातार और ज़रूरत-आधारित पहलें एमईसीएल के रणनीतिक, समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण को दिखाती हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर सार्थक प्रभाव सुनिश्चित करती हैं, साथ ही समावेशी विकास और ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मज़बूत करती हैं।

13. राष्ट्रीय खनिज भंडारण में योगदान

एमईसीएल की अन्वेषण गतिविधियों ने राष्ट्रीय खनिज भंडारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे लगभग 7133 मिलियन टन खनिज भंडार जुड़े हैं। इनमें कोयला, लिग्नाइट, लौह

अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज, तांबा, ग्रेफाइट, पोटाश और रॉक फॉस्फेट जैसे प्रमुख खनिज शामिल हैं, जो भारत के खनिज संसाधनों में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में MECL की स्थिति को मजबूत करते हैं।

14. **लाभांश**

भारत सरकार को ₹212 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, जो ₹25.34 करोड़– पीएटी का 30%–था, भेजा गया, जो एक लाभदायक और जिम्मेदार सीपीएसई के रूप में एमईसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

15. डिजिटल परिवर्तन: एमईसीएल ई-ऑफिस का उद्घाटन-

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एमईसीएल की प्रमुख आईटी उपलब्धियों में एंटरप्राइज सिस्टम और भूवैज्ञानिक डेटा प्लेटफॉर्म का निर्बाध संचालन और निवारक रखरखाव, उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचा और साइबर सुरक्षा, वित्तीय और नमूना प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बीजी और ईएमडी ट्रैकिंग और रेफरी नमूना ट्रैकिंग पोर्टल का विकास, और जीजीआईडब्ल्यू 3.0-अनुरूप वेबसाइट का नया रूप और एक उन्नत ईपीएफ ट्रस्ट प्रबंधन एप्लिकेशन का मूल्यांकन जैसी चल रही डिजिटलीकरण पहलें शामिल थीं, जिससे परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और व्यावसायिक निरंतरता में काफी सुधार हुआ।

16. **उद्योग जुड़ाव और कार्यशालाएं**

एमईसीएल ने 2025 में कार्यशालाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से उद्योग के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया:

➢ 6 4वींसीजीपीबी बैठक, भुवनेश्वर (19 जनवरी 2025)

- महत्वपूर्ण खनिज नमूनों और हैंडहेल्ड XRF तकनीक का प्रदर्शन किया।

➢ भारत पर्व, नई दिल्ली (26-31 जनवरी 2025)

- भारत की खनिज विरासत और सतत विकास में MECL के योगदान पर प्रकाश डाला।

➢ नेक्स्टजेन जियोफिजिक्स, GSITI हैदराबाद (09-10 जून 2025)

- गामा रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तकनीक का लाइव प्रदर्शन।

➢ दूसरा पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों का सम्मेलन, गुवाहाटी (27-28 जून 2025)

- पूर्वोत्तर खनिज क्षमता का प्रदर्शन किया।

➢ आईआईटीF-2025, नई दिल्ली

- आधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल कोर सैंपल, प्रिसिशन मैपिंग और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए।
- भारत के मिनरल रिसोर्स डेवलपमेंट में एमईसीएल की अहम भूमिका और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए इसकी सहायता पर ज़ोर दिया गया।

17: पुरस्कार और सम्मान

➢ आंतरिक हिंदी पत्रिका "खनिज प्रवाह" को नाराकस द्वारा तीसरा पुरस्कार दिया गया, जो पीएसयू में हिंदी को बढ़ावा देने में इसकी उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

➢ एमईसीएल में मैनेजर (केमिकल) डॉ. दीप्ति रहांगडाले को "सेलिब्रेटिंग विमेन इन माइनिंग" कार्यक्रम में उन्नत खनिज और कोयला विश्लेषण में उनकी उत्कृष्ट विशेषज्ञता के लिए महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खनन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति एमईसीएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एमईसीएल का वित्त वर्ष 2025-26 में, 30 नवंबर 2025 तक का प्रदर्शन, भारत के खनिज क्षेत्र में एक रणनीतिक और उद्योग-केंद्रित भागीदार के रूप में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है। मजबूत अन्वेषण और वित्तीय परिणाम प्राप्त करने के अलावा, एमईसीएल ने अपनी विविध सेवाओं के विवरण का विस्तार किया है - जिसमें भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, कोर ड्रिलिंग, संसाधन मूल्यांकन, तकनीकी परामर्श, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय विश्लेषण, रिग मरम्मत और इंस्ट्रूमेंटेशन सहायता शामिल हैं - जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों को नवीन समाधानों के साथ मिलाकर, एमईसीएल सतत खनिज विकास का समर्थन करता है, महत्वपूर्ण खनिज नीलामी को सुविधाजनक बनाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है, और उच्च-मूल्य वाली, अनुकूलित सेवाएं प्रदान करता है जो खनन और अन्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र में परिचालन दक्षता को बढ़ाती हैं।

कोयला क्षेत्र, धनबाद में खोजपूर्ण ड्रिलिंग गतिविधि

वार्षिक परियोजना प्रबंधक बैठक

गामा विकरण स्पेक्ट्रोमीटर के लिए प्रशिक्षण

एमईसीएल को ‘‘न्यूनतम 4 घंटे सीखने का लक्ष्य’’ हासिल करने के लिए नेशनल लर्निंग वीक में पहला स्थान हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है।

लाइब्स की स्थापना

	Exploration for Lignite in Jammu & Kashmir
	Hon,ble Union Minister, Shri Arjun Ram Meghwal visited Bikaner potash Exploration Site
MoU with Catamarca Province, Argentina	MoA with GSI
MoU with OIL	MoU with NML -CSIR

जे. **भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)**

आईबीएम के मुख्य कामों के अलावा, यानी अलग-अलग क्षेत्र निरीक्षण, ओर ड्रेसिंग जांच, कुछ बड़ी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. **खानों की स्टार रेटिंग के ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से सतत विकास फ्रेमवर्क (एस डी एफ) का कार्यान्वयन:**

• प्रदर्शन वर्ष 2023-24 के लिए, 95 पांच-स्टार रेटेड खानों को 7 जुलाई, 2025 को जयपुर में सम्मानित किया गया। इस समारोह में कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे उपस्थित थे।

• 95 पांच-स्टार रेटेड खानों में से 3 खानों को 'ग्रीन माइनिंग' में असाधारण प्रदर्शन के लिए सात-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। इस वर्ष का विषय, "ग्रीन माइनिंग", कार्बन फुटप्रिंट में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, ग्रीन माइनिंग प्रथाओं, स्थायी लॉजिस्टिक्स और पारिस्थितिक बहाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित था। यह पहल न केवल पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन मानकों को बढ़ाती है, बल्कि आर्थिक विकास को पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ एकीकृत करने में भारत के नेतृत्व को भी मजबूत करती है।

स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू होने के बाद से साल के हिसाब से 5 स्टार रेटेड खदानों की जानकारी नीचे दी गई है:

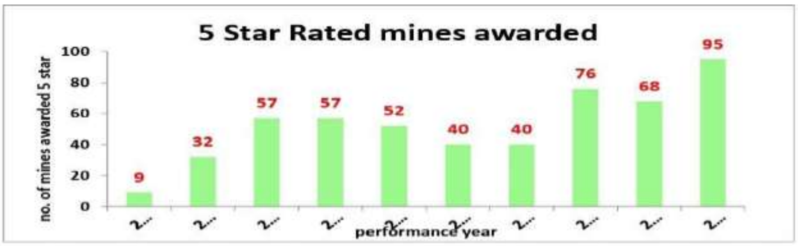

7.7.2025 को जयपुर में फाइव स्टार रेटेड खदानों का सम्मान समारोह।

2. खनन निगरानी तंत्र (एम एस एस) एक उपग्रह-आधारित निगरानी तंत्र है जो ऑटोमैटिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन तकनीक के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों को रोककर एक ज़िम्मेदार खनन प्रशासनिक तंत्र बनाता है। खनन निगरानी तंत्र का इस्तेमाल

करके, 2022-23 में चौथे चरण के दौरान, बड़े खनिजों के लिए 138 ट्रिगर जेनरेट किए गए। अब तक, 40 ट्रिगर वेरिफाई किए गए हैं और 07 मामलों में बिना इजाज़त खनन का पता चला है। 5वें चरण के दौरान, सक्षम प्राधिकरण यानी खान मंत्रालय द्वारा 2023-24 के दौरान तैयार किए गए 157 ट्रिगर को एमएसएस पोर्टल पर अपलोड करने की मंज़ूरी मिलने के बाद, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को सत्यापन और उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया।

खनन निगरानी तंत्र

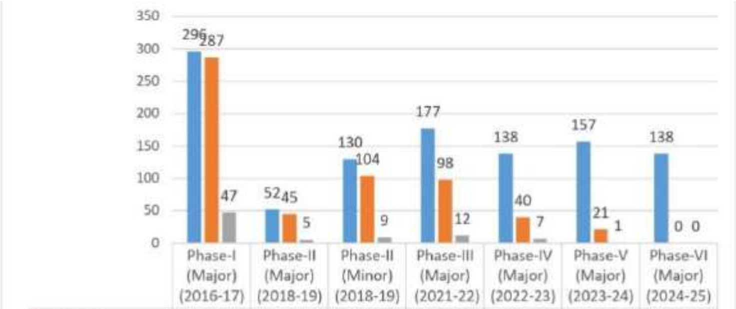

	Phase-I (Major) (2016-17)	Phase-II (Major) (2018-19)	Phase-II (Minor) (2018-19)	Phase-III (Major) (2021-22)	Phase-IV (Major) (2022-23)	Phase-V (Major) (2023-24)	Phase-VI (Major) (2024-25)
Triggers Generated	296	52	130	177	138	157	138
Triggers Verified	287	45	104	98	40	21	0
Unauthorized Mining confirmed	47	5	9	12	7	1	0

3. **माइनिंग टेनमेंट सिस्टम**

- माइनिंग टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस का एक प्रमुख परियोजना है और यह अपनी तरह का दुनिया का पहला अनोखा एप्लीकेशन है, जो मिनरल कंसेशन लाइफ साइकिल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एमटीएस के साथ, आईबीएम का दृष्टिकोण कोर मॉड्यूल की पूरी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना है, जिससे एक वर्कफ़्लो-आधारित सिस्टम शुरू किया जा सके और इसके कामकाज में दक्षता, सेवा वितरण और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
- इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, आईबीएम जहाँ भी ज़रूरी हो, सुधार करने की भी योजना बना रहा है। निम्नलिखित मॉड्यूल लॉन्च/अपग्रेड किए गए।

(i) **नोटिस/रिपोर्ट: -** 20/01/2025 को तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2025, कोणार्क, ओडिशा में लॉन्च किया गया

(ii) **संशोधन -** 20/01/2025 को तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2025, कोणार्क, ओडिशा में लॉन्च किया गया।

(iii) **खनिज प्रसंस्करण -** 20/01/2025 को तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2025, कोणार्क, ओडिशा में लॉन्च किया गया, जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के विज़न को पूरा करता है।

(iv) **निरीक्षण -** 20/01/2025 को तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्री सम्मेलन 2025, कोणार्क, ओडिशा में लॉन्च किया गया।

तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन में एम टी एस मॉड्यूल का शुभारंभ

• **प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड –** नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस (एन ए ई जी) 2025 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड, जिसे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) द्वारा प्रस्तुत किया गया।

एमटीएस (आई बी एम) को ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एन ए ई जी) 2025 में गोल्ड अवार्ड मिला।

- **अन्य लाभ-**
  - **(i)** अलग-अलग हितधारकों के लिए कंप्लायंस का बोझ कम हुआ और बिजनेस करना आसान हुआ।
  - (ii) कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है। जैसे, पहले माइनिंग प्लान एक मोटी कागज़ की किताब होती थी, अब यह काम पेपरलेस है।
  - (iii) क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मीका, बेराइट्स माइनिंग लीज होल्डर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को आसान बनाकर उन्हें सुविधा दी गई।
  - (iv) माननीय मंत्री का डैशबोर्ड डेवलप किया गया।
  - (v) ड्रोन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का अपग्रेडेशन और डैशबोर्ड। (vi)
  - (vi) एमआईडीपीएएस मॉड्यूल में उन्नयन से वर्चुअल निगरानी आसान हुए।

(vii) खनिज प्रसंस्करण मॉड्यूल को नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ जोड़ा गया, जिसमें सभी आरओ, आरएमपीएल लैब्स, जेएनआरडीसी और जीएमआरडीसी द्वारा सैंपल रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी गई।

(viii) अपतटीय खनिज के लिए पंजीकरण मॉड्यूल का विकास

(ix) पीएम गति शक्ति के साथ API (WIP)।

(x) खनन के यूनिफाइड पोर्टल के साथ API (WIP)।

4. **UAV सर्वे से जुड़ी गतिविधियाँ:** आईबीएम ने एमसीडीआर, 2017 के नियम 34A के सब-रूल (5) के तहत ड्रोन सर्वे करने और माइनिंग एरिया की डिजिटल एरियल इमेज आईबीएम को देने करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए हैं। एमसीडीआर 2017 के नियम 34A के तहत लीजधारकों द्वारा सबमिट किए गए ड्रोन/सैटेलाइट डेटा की प्राप्ति का एक रजिस्टर आईबीएम में मेंटेन किया जा रहा है। आईबीएम ने अपने हेडक्वार्टर में हाल ही में 131 टेराबाइट क्षमता वाले अपने सबसे बड़े डेटा सेंटर शुरू किए हैं। वर्ष 2025 के दौरान, एमसीडीआर2017 के नियम 34A के तहत आईबीएम के ड्रोन डेटा

मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) पोर्टल में 1326 खानों की डिजिटल एरियल (ड्रोन और सैटेलाइट) फोटो ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं।

मिडपास पोर्टल में ड्रोन डेटा इमेजरी का विश्लेषण

5.खानों का राष्ट्रीय भू-रासायनिक डेटाबेस और पुराने डंप, टेलिंग और प्रसंस्कृत कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता

विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर अपने राष्ट्रीय एजेंडे को मजबूत किया है, जिसमें पुराने डंप, टेलिंग और प्रसंस्करण कचरे जैसे स्मेल्टर स्लैग से सेकेंडरी संसाधनों का इस्तेमाल करने पर खास ध्यान दिया गया है। इस क्षमता को पहचानते हुए, खान मंत्रालय ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आई बी एम) को पूरे देश में खनन वैल्यू चेन में बनने वाले कचरे के ढेर, खदान के कचरे और प्रोसेसिंग कचरे का देशव्यापी मूल्यांकन करने का काम

सौंपा, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी और खदान के कचरे और टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने की संभावना का पता लगाया जा सके।

इस पहल के तहत, इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस ने क्रोमाइट, कॉपर, टिन, लेड और जिंक, बॉक्साइट, फ्लोराइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट, सोना और बैराइट सहित दस मुख्य कमोडिटीज़ को कवर करते हुए एक शुरुआती स्कोपिंग स्टडी की। देश भर की 311 खानों, 32 बेनिफिशिएशन और 27 स्मेल्टिंग और रिफाइनरी प्लांट से कुल 2,383 सैंपल इकट्ठा किए गए और अलग-अलग तत्वों के लिए उनका विश्लेषण किया गया।

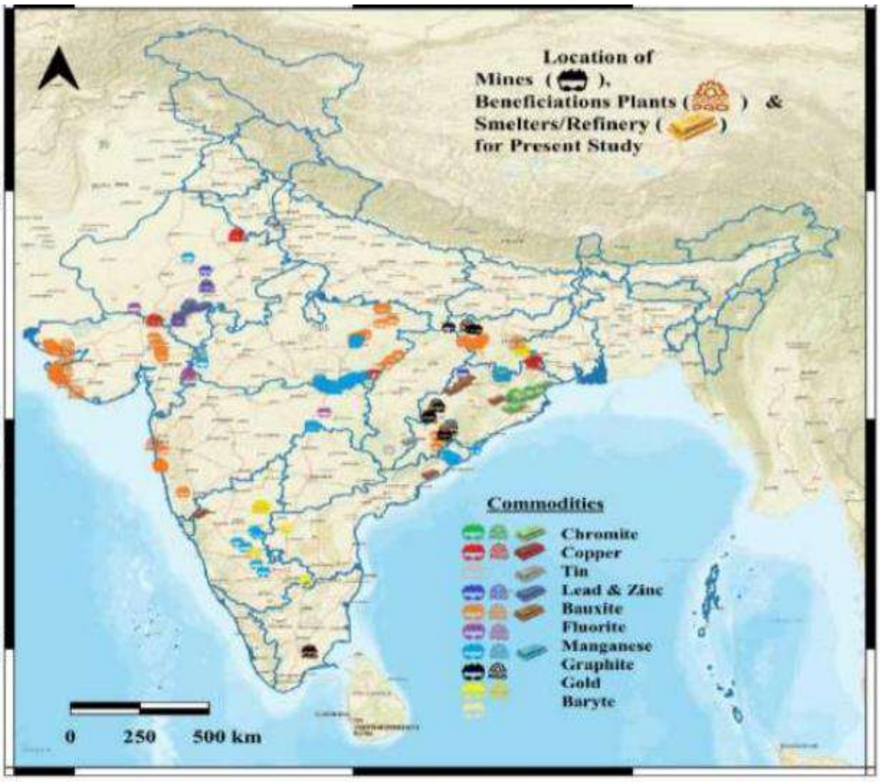

क्रोमाइट वेस्ट डंप से निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम समूह के तत्व (पी जी ई); बॉक्साइट खदानों से गैलियम, वैनेडियम और दुर्लभ भूमि तत्व (आर ई ई); कॉपर स्मेल्टर से मोलिब्डेनम, सेलेनियम, टेल्यूरियम और प्लेटिनम ग्रुप ऑफ़ एलिमेंट्स (PGEs); लेड-जिंक स्मेल्टर से कैडमियम, एंटीमनी और बिस्मथ; टिन स्लैग से नाइओबियम और टैंटलम; और फ्लोराइट खदानों और बेनिफिशिएशन प्लांट से दुर्लभ भूमि तत्व (आर ई ई) जैसे विभिन्न वेस्ट स्ट्रीम में महत्वपूर्ण खनिजों की आशाजनक खोजों के आधार पर, इन महत्वपूर्ण खनिज हॉटस्पॉट से उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिजों को वापस प्राप्त करने की संभावना के लिए आगे विस्तृत काम करने हेतु हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

इस पहल के हिस्से के रूप में, भारतीय खनन ब्यूरो (आई बी एम) और राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशंस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से 09 मई 2025 को नागपुर में "खदान टेलिंग और कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण: अवसर और चुनौतियाँ" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया गया था।

6. माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे का नागपुर स्थित आईबीएम मुख्यालय का दौरा-

नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय में अपने पहले दौरे पर, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत एक पौधा लगाया। उनके साथ भारतीय खान ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

आईबीएम मुख्यालय के अपने दौरे के दौरान, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे को आईबीएम की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला का दौरा कराया गया। यह प्रयोगशाला खनन क्षेत्रों की निगरानी और खनिज संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य खनन भूविज्ञानी श्री एस.के. अधिकारी और आरएमजी श्री टी.के. सोनारकर ने श्री दुबे को जीआईएस प्रयोगशाला के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ने आईबीएम के खनन पट्टा प्रणाली प्रकोष्ठ का भी दौरा किया, जहां खान नियंत्रक (एमटीएस) श्री पुष्पेंद्र गौर ने उन्हें इस प्रमुख परियोजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। यह परियोजना सुव्यवस्थित अनुमोदन, डिजिटल अनुपालन और अधिक पारदर्शिता के साथ खनन क्षेत्र में व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करती है।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने 28 नवंबर 2025 को नागपुर स्थित भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महानियंत्रक (प्रभारी) श्री पंकज कुलश्रेष्ठ ने मंत्री जी को आईबीएम के विभिन्न कार्यों, उसकी उपलब्धियों और खनन क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान, मंत्री जी ने जीवनयापन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, आईबीएम मुख्यालय, नागपुर में

7. औसत विक्रय मूल्य (एएसपी): आईबीएम ने हाल ही में अपने एमटीएस परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए एक नया औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) मॉड्यूल शुरू किया है। माननीय खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 23.01.2024 को राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां प्रस्तुत रिटर्न का वास्तविक समय डेटा रिटर्न मॉड्यूल (आईबीएमreturns.gov.in) से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाता है। कुल मिलाकर, इस प्रणाली ने व्यापार करने में आसानी प्रदान की और एएसपी उत्पन्न करने में लगने वाले समय को कम किया। यह नया एएसपी मॉड्यूल आईबीएम को खनिजों के औसत विक्रय मूल्य जारी करने में लगने वाले समय के अंतर को कम करने में सक्षम बनाता है। वर्तमान वर्ष 2025 के दौरान, सितंबर 2025 तक खनिजों और धातुओं के औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) को आईबीएम वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

8. आईबीएम ने इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 (खंड 1 से 3), एनुअल बुलेटिन ऑफ माइनिंग लीज, कम्पोजिट लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और ऑक्शन - 2024 जैसी महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रकाशित की हैं, जिन्हें आईबीएम वेबसाइट पर जारी और अपलोड किया गया है। साथ ही, सभी हितधारकों के हित में तकनीकी डेटा प्रसारित करने के लिए सितंबर 2025 तक के मिनरल प्रोडक्शन के मासिक आँकड़े (एमएसएमपी) भी प्रकाशित किए गए हैं।

9. मानव संसाधन विकास: मानव संसाधनों की क्षमता निर्माण के अंतर्गत, वर्ष 2025 (नवंबर 2025 तक) में, आईबीएम ने 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 847 आईबीएम कर्मचारियों, 834 उद्योग कर्मियों और 65 राज्य डीजीएम अधिकारियों ने भाग लिया और 25,77,728/- रुपये (पच्चीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ अट्ठाईस रुपये मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ।

10. आईबीएम के दो अधिकारियों को माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा 06.03.2025 को हैदराबाद में आयोजित "खनन क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान" कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, अधीक्षक, रसायनज्ञ और श्रीमती प्रीति मिश्रा, उप अयस्क प्रसंस्करण अधिकारी, आधुनिक खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला (एमएमपीएल) और पायलट प्लांट, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग (एमपीडी) नागपुर से उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

11. भारतीय खान ब्यूरो ने 1 मार्च 2025 को अपने 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन को खनिज दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और नागपुर स्थित मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और अयस्क प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं में 1 मार्च 2025 को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। खनिज दिवस समारोह से पहले, 28 फरवरी 2025 को आईबीएम (मुख्यालय) में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आईबीएम (मुख्यालय) की पहल के अनुरूप, जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने भी स्थापना दिवस से

पहले एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आईबीएम परिवार ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कर्मचारियों ने इस शिविर में रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

K भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 1,156 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें एम-I (बेसलाइन भूविज्ञान डेटा सृजन) के अंतर्गत 300 परियोजनाएं, (खनिज अन्वेषण) के अंतर्गत 435 परियोजनाएं, एम-III (भूसूचना विज्ञान) के अंतर्गत 67 परियोजनाएं, एम-IV (मौलिक एवं बहुविषयक भूविज्ञान अनुसंधान) के अंतर्गत 165 परियोजनाएं, और एम-V (प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण) के अंतर्गत 189 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ii) मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में, जीएसआई ने 1,122 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें M-I (बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जेनरेशन) में 243, M-II (मिनरल एक्सप्लोरेशन) में 468, M-III (जियोइन्फॉर्मेटिक्स) में 75, M-IV (फंडामेंटल और मल्टीडिसिप्लिनरी जियोसाइंस रिसर्च) में 176, और M-V (ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग) में 160 प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

(iii) **बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जेनरेशन (मिशन-I)** के तहत, GSI ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान निम्नलिखित सर्वे पूरे किए हैं:

a. स्पेशलाइज्ड थीमेटिक मैपिंग-22,800 वर्ग किमी के टारगेट में से 29,964 वर्ग किमी (1:25,000 स्केल पर)।
b. नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग और कोर डेक्कन ट्रैप का जियोकेमिकल असेसमेंट-58,000 वर्ग किमी के टारगेट में से 65,072 वर्ग किमी (1:50,000 स्केल पर)।
c. नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग-1,28,000 वर्ग किमी के टारगेट में से 1,63,922 वर्ग किमी (1:50,000 स्केल पर) इन-हाउस संसाधनों के माध्यम से। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2,02,484 वर्ग किमी क्षेत्र पूरा किया गया।
d. नेशनल एयरो-जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम (एनएजीएमपी), जीएसआई का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य पहले से पहचाने गए भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्र पर एक समान एयरो-जियोफिजिकल डेटा प्राप्त करना है। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान, आगे के सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एनएजीएमपी सर्वे के माध्यम से लगभग 86,107 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर किया गया है।

(iv) **प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन (मिशन-II)** के तहत, जीएसआई ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए हैं:

a) बड़े पैमाने पर मैपिंग - 17,725 वर्ग किमी के कुल लक्ष्य में से 18549.40 वर्ग किमी (1:10,000/12,500 पैमाने पर)।
b) महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (सीएसएम) की खोज को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय सत्र 2024-25 के दौरान 195 सीएसएम परियोजनाएं निष्पादित की गईं और वर्तमान क्षेत्रीय सत्र 2025-26 में 230 सीएसएम परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें क्षेत्रीय सत्र 2025-26 के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) पर 93 अन्वेषण कार्यक्रम भी शामिल हैं।

आरईई अन्वेषण कार्यक्रम का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है: 17-राजस्थान, 11-झारखंड, 10-पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय और बिहार में 6-6, तेलंगाना और ओडिशा में 5-5, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4-4, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 3-3, और त्रिपुरा और केरल में एक-एक।

c) बड़े क्षेत्रों की खोज के लिए निजी और अन्य अन्वेषण एजेंसियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, जीएसआई ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट (एनएमईडीटी) को 7 क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण (आर एम टी) ब्लॉक प्रदान किए हैं ताकि अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों (एन पी ई ए) द्वारा एनएमईडीटी कोष के समर्थन से अन्वेषण किया जा सके। इनमें से 5 ब्लॉक पहले ही एन पी ई ए द्वारा ले लिए गए हैं। जी एस आई ने राजस्थान के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में 15-जी3 खनिज ब्लॉक भी बनाए हैं और एनएमईडीटी को सौंप दिए हैं ताकि एनपीईए द्वारा एक पहचाने गए बड़े खनिज भंडार की खोज में तेजी लाई जा सके।

d) जनवरी 2025 में, जीएसआई ने कुल 63 ब्लॉक सौंपे हैं। जियोलॉजिकल रिपोर्ट (जी 2/जी3) खान मंत्रालय और राज्य सरकार को सौंपी गईं। 63 जियोलॉजिकल रिपोर्ट (जीआर) में से, 39 जीआर (22-चूना पत्थर, 05-लौह अयस्क, 04-तांबा, 04-मैंगनीज, 03-सोना, और 1-जिप्सम) संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दी गईं और महत्वपूर्ण खनिजों की 24 जीआर (6-वैनेडियम, 6- आरईई , 4-ग्रेफाइट, 4-पोटाश, और कोबाल्ट और मोलिब्डेनम में से प्रत्येक 1) एमओएम को सौंप दी गईं। साथ ही, जीएसआई ने 19 जियोलॉजिकल मेमोरेंडम (जीएम/जी4) राज्य सरकार और एमओएम को सौंपे। 19 जीएम में से, 8 संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिए गए (3-बॉक्साइट अयस्क, और तांबा, लौह अयस्क, सीसा, चूना पत्थर और एल्यूमिनस लेटराइट में से प्रत्येक 1) और 11 जीएम एमओएम को सौंप दिए गए (4-वैनेडियम, 2-ग्रेफाइट और कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, निकल, पोटाश और आरईई में से प्रत्येक 1)। नवंबर 2025 के महीने में, 7 और जीआर (3-वैनेडियम और ग्लौकोनाइट, निकल, आरईई और टंगस्टन में से प्रत्येक 1) और 1 जीएम (टाइटेनियम) एमओएम को सौंप दिए गए।

e) जीएसआई ने जनवरी 2025 के महीने में कोयला मंत्रालय को 04 संसाधन-युक्त कोयला ब्लॉक भी सौंपे हैं।

f) इसके अलावा, जीएसआई ने अक्टूबर 2025 के महीने में 11 अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) ब्लॉक भी सौंपे हैं।

g) जीएसआई ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक हाइड्रोजन संसाधन की खोज की है, जो फरवरी 2025 के महीने में भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन की पहली खोज है।

ओफियोलाइट ग्रुप की अल्ट्रामाफिक और मैफिक चट्टानों के ऊपर थ्रस्ट ज़ोन के अंदर फ्रैक्चर प्लेन से निकलने वाले गैस के बुलबुले, 75% एलईएल (30000 ppm) H2 तक का पता लगाते हैं, कोडियाघाट क्षेत्र, दक्षिण अंडमान।

(v) **जियोइन्फॉर्मेटिक्स (मिशन-III)** के तहत, जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं या प्रगति पर हैं:

a) जीएसआई नेक्स्ट जेनरेशन पोर्टल (पोर्टल-एनजी) विकसित कर रहा है, जो ग्राहक सुलभ उपयोगी होगा, जिसकी पहुंच सरल होगी और इसमें ऐप-आधारित सेवाओं के एकीकरण की सुविधा होगी और यूज़र की ज़रूरतों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के अनुसार उन्नयन किया जा सकेगा।

b) राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक डेटा कोष (एनजीडीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान 5,290 रिपोर्ट (जीएसआई: 3330, स्टेकहोल्डर: 1960) अपलोड की गई हैं, जिससे एनजीडीआर पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट की कुल संख्या 15,741 हो गई है। (जी एस आई: 12732, हितधारक: 3009)। इस अवधि के दौरान, 22 नए स्टेकहोल्डर ने भी एनजीडीआर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के लिए एनजीडीआर पोर्टल के तहत पंजीकरण कराया। जीएसआई के ये दोनों जियोस्पेशियल पोर्टल (एनजीडीआर और भूकोश) जनता को बिना किसी प्रतिबंध के और हर महीने लगभग 9000 यूज़र इन पोर्टलों से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं।

c) जीएसआई ने एनआरएससी इसरो के सहयोग से, एपीआई के माध्यम से भूनीधि ऐप डेटा को एनजीडीआर में एकीकृत किया, जिससे सभी मौसमों के लिए एलआईएसएस -3 और एलआईएसएस-4 डेटा तक मुफ्त पहुंच प्रदान की गई। मुफ्त डेटा एक्सेस के लिए एपीआई का उद्घाटन 16.01.2025 को किया गया था।

d) इन-हाउस साइंटिफिक जर्नल 'इंडियन जर्नल ऑफ़ जियोसाइंसेज' का स्पेशल इश्यू जीएसआई के 175 साल' वॉल्यूम-79 (i) अगस्त, 2025 में श्री असित साहा, डायरेक्टर जनरल, GSI द्वारा जारी किया गया।

e) जीएसआई ने इस दौरान 25 प्रमुख प्रकाशन प्रकाशित किए, जैसे इंडियन जर्नल ऑफ़ जियोसाइंसेज, गोंडवाना बेसिन ऑफ़ इंडिया, झारखंड में सोने की खोज की स्थिति आदि।

f) जीएसआई ने इस दौरान 17 मैप जारी किए, जैसे 1:2M स्केल का मेटालोजेनिक मैप ऑफ़ इंडिया, 1:250K जिलों का मैप आदि और 1:5M स्केल पर भारत का क्वाटरनरी जियोलॉजिकल मैप भी जारी किया।

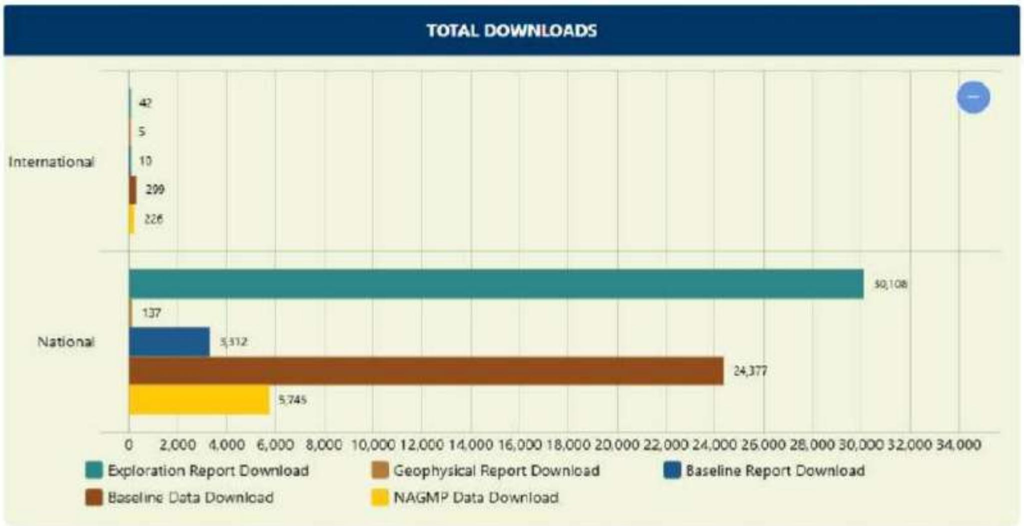

पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा NGDR पोर्टल से डाउनलोड स्थिति

Downloads by:

National Agencies: Adani Enterprise, AMD, CMPDIL, Coal India, NGRI, Fomento, Engeotech, Geoexpore, Geomarine, Geovale, Gemco Kati, Hindalco, HZL, IDPeX, IBM, ISRO, JSW, KIOCL, KPMG, Maheswari Mining, MECL, ONGC, Neurons AI, NMET, NMDC, Novomine, OMC, Tata Steel, SCCL

Academic Org: Adamas University, Andhra University, Benaras Hindu University, Aligarh Muslim University, Birbal Sahni Institute, IIT Bombay, ISM Dhanbad, IIT Kharagpur, IIT Roorkey, Lucknow University, NRSC

DGMs: Gujrat, Rajasthan, Tamilnadu, J&K, Kerala, Chhattisgarh, MP, Assam, Odisha, Karnataka, Jharkhand, Andhra Pradesh.

ALS Golspot, Canada
Queen's University, Canada
Tim Archer, Natural Resource Consulting, United Kingdom
University of Western Australia
Radixplore, Australia
Lombardi Group, Switzerland
Bell Geospace, USA
Bandung Institute of Technology, Indonesia
Ivan Portnov , Russia
Universite de Poitiers, France
University of the Free State, Bloemfontein, South Africa

Foreign Organizations	Country
National University of Rosario	Argentina
University of Western Australia	Australia
RadiXplore	Australia
Queensland University of Technology	Australia
Fortescue Metals Group	Australia
Sibelco	Belgium
UniLaSalle	France
CAU Kiel	Germany
Beak Consultants GmbH	Germany
Bandung Institute of Technology	Indonesia
Mineral exploration corporation limited	Iran
Adepth minerals as	Norway
Universite de Poitiers	Ukraine
Reid Geophysics Limited	United Kingdom
Natural Resource Consulting	United Kingdom
Getech	United Kingdom
University of Exeter	United Kingdom
University of California	United States
SLB	United States
Stanford	United States
University of Maryland College Park	United States
CSM	United States
LithoAyas LLC	United States

पंजीकृत उपयोगकर्ता एनजीडीआर पोर्टल से विवरण डाउनलोड कर सकते हैं।

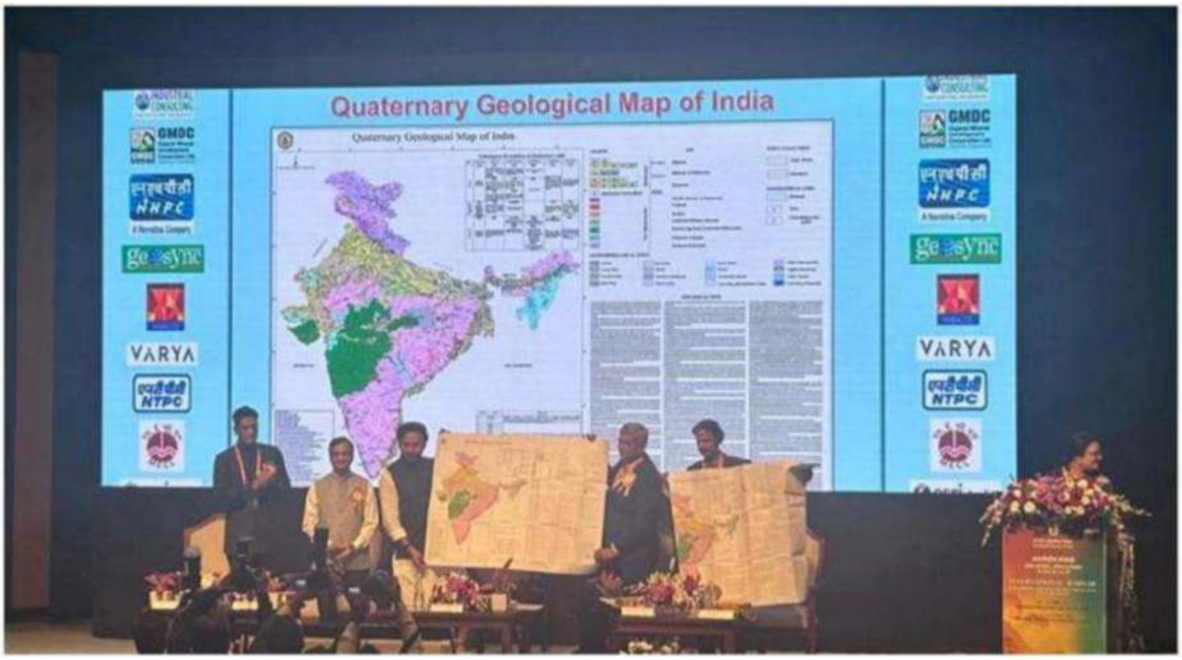

माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री द्वारा चतुर्थक भूवैज्ञानिक मानचित्र का विमोचन।

(vi) **फंडामेंटल और मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस (मिशन-IV)** के तहत, जीएसआई देश भर में और साथ ही ध्रुवीय क्षेत्र (यानी अंटार्कटिका) में सार्वजनिक हित के भूविज्ञान और अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। 2024-25 में, जीएसआई ने जियोटेक्निकल और भू-खतरा प्रबंधन के तहत 83 परियोजनाएं, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन की 33 परियोजनाएं और 49 मौलिक भूविज्ञान और अनुसंधान परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। ये कार्य पनबिजली और सिंचाई परियोजनाओं, भूस्खलन और ढलान स्थिरता मूल्यांकन, भूकंपीय खतरा मूल्यांकन, भूजल और भू-पर्यावरण अध्ययन, महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण, जीवाश्म विज्ञान, तलछट विज्ञान और पर्यावरणीय पुनर्निर्माण में फैले हुए हैं, जो बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा शमन और संसाधन प्रबंधन के लिए सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में, जीएसआई ने देश भर में 181 परियोजनाएं शुरू कीं। इनमें से 130 से अधिक परियोजनाएं भूस्खलन गतिशीलता, जीएलओएफ, भूजल संदूषण और पर्यावरणीय अध्ययन पर काम के माध्यम से सीधे समाज को लाभ पहुंचाती हैं, जबकि 26 परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में अनुसंधान और विकास का समर्थन किया, जो भूविज्ञान नवाचार और राष्ट्रीय विकास के प्रति जीएसआई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान निम्नलिखित हासिल किया गया है:

a) रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आगे बढ़ाना: जीएसआई ने हिमनद विज्ञान, जल विज्ञान, जीएलओएफ और भूस्खलन अध्ययनों को बढ़ाने के लिए हाइड्रोलॉजिकल और वर्षा डेटा के वास्तविक समय साझाकरण के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सीएनआर-आईआरपीआई, इटली के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से, जीएसआई के लेब्स मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम और एमआईएनईएमए (रवांडा) से प्रशंसा शामिल है, जो भूस्लन पूर्वानुमान विज्ञान में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है।

b) भू-तकनीकी विशेषज्ञता के साथ रणनीतिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का समर्थन: GSI ने जम्मू और कश्मीर (चेनानी-नाशरी, वैलू), लद्दाख (फोटू ला), असम और वाराणसी-कोलकाता गलियारे में प्रमुख सुरंग परियोजनाओं के लिए डीपीआर की समीक्षा करके रणनीतिक गलियारों में सड़क और सुरंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। जीएसआई ने हाइड्रोपावर, सड़क, रेल और जल-संसाधन परियोजनाओं के लिए 28 जियोटेक्निकल जांच भी कीं और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार जियोटेक्निकल सहायता प्रदान करने के लिए एनएचएआई और एमओआरटीएच के साथ सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए।

c) राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (एनएलएफसी) भारत की भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (लेव्स) का विस्तार और सुदृढ़ीकरण: जीएसआई द्वारा 2024 में स्थापित भारत के पहले राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ने वर्ष 2025 में 11 राज्यों के 16 से 21 जिलों तक अपना कवरेज बढ़ाया, और भुसंकेत पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक समय के परिचालन और प्रायोगिक बुलेटिन जारी किए। पूर्वानुमान को मजबूत करने के लिए, जीएसआई ने केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र, नागालैंड और उत्तराखंड एसडीएमए, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इटली के CNR IRPI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वास्तविक समय के वर्षा डेटा और उन्नत भविष्यवाणी मॉडल को एकीकृत किया गया।

d) पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को भूवैज्ञानिक सहायता के माध्यम से भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को मजबूत करना: जीएसआई ने 2025 में सीईए द्वारा स्वीकृत 10,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 8 पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए समय पर भूवैज्ञानिक और जियोटेक्निकल मूल्यांकन प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मूल्यांकनों ने तेजी से मंजूरी और मजबूत डीपीआर को सक्षम बनाया। 2025-26 के लिए पाइपलाइन में 13 और पीएसपी (22 जीडब्ल्यू) के साथ, जीएसआई भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करना जारी रखे हुए है।

e) पूर्वोत्तर और हिमालयी बेल्ट के नाजुक क्षेत्रों में भूकंपीय और भूकंपीय खतरे के अध्ययन को आगे बढ़ाया गया। तीस्ता बेसिन, नर्मदा घाटी और कैम्बे बेसिन में सक्रिय फॉल्ट मैपिंग, पेलियोसिस्मिक आकलन और GPS स्ट्रेन निगरानी की गई। कोलासिब (मिजोरम), उदयपुर (त्रिपुरा) और ओंगोल (आंध्र प्रदेश) में भूकंपीय माइक्रोज़ोनेशन किया गया, जबकि नागपुर, महाराष्ट्र में सूक्ष्म भूकंप निगरानी की गई।

f) बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और भारी धातुओं पर केंद्रित भूजल प्रदूषण अध्ययन किए गए। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान भू-वैज्ञानिक और मानवजनित दोनों तरह से की गई, जिससे पर्यावरण प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

g) अंडमान, कोंकण और ओडिशा में तटीय अध्ययनों में मॉर्फोडायनामिक्स, कटाव-जमाव पैटर्न और समुद्र तट प्लेसर संरचना की जांच की गई। अंटार्कटिका (निवलिसन, लारसेमैन हिल्स, लोमोनोसोव पर्वत) में हिमनद अनुसंधान में बर्फ द्रव्यमान संतुलन, पीछे हटने और

पर्वत निर्माण विस्तार का आकलन किया गया। हिमालयी अध्ययनों ने अरुणाचल प्रदेश में लेट क्वाटरनरी हिमनदी, मोरेन, आइस वेज स्यूडोमॉर्फ और पेलियो पर्माफ्रॉस्ट साक्ष्य का पुनर्निर्माण किया।

h) उत्तर अंडमान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पेग्माटाइट, ग्रेनाइट, कार्बोनेटाइट और अल्ट्रामैफिक जैसे अलग-अलग रॉक सूट में मिनरलाइज़ेशन की पहचान और कैरेक्टराइज़ेशन के लिए महत्वपूर्ण मिनरल स्टडीज़ की गईं। कच्छ, मेघालय और वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटन में REE-एनरिच्ड ज़ोन की खोज की गई। अन्य महत्वपूर्ण मौलिक रिसर्च में भारतीय क्षेत्र में गिरे उल्कापिंड के कैरेक्टराइज़ेशन के लिए प्लैनेटरी साइंस स्टडीज़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में जीवाश्मों के डॉक्यूमेंटेशन, पेलियोएनवायरनमेंट, बायोस्ट्रेटिग्राफी और पेलियोक्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करते हुए पेलियोन्टोलॉजिकल स्टडीज़ शामिल थीं। सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न और कोस्टल इंडिया में सेडिमेंटोलॉजिकल और जियोकेमिकल रिकंस्ट्रक्शन किए गए, जबकि सह्याद्री बेसाल्ट का CO_2 सीक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल के लिए अध्ययन किया गया। इन प्रयासों से प्रमुख जर्नल्स में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हुए।

Visit of British High Commissioner to the National Meteorite Repository, CHQ, Kolkata

Visit of delegates from British Geological Survey to the National Meteorite Repository, CHQ, Kolkata

vii) **ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण (मिशन-V)** के तहत, जीएसआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जीएसआईटीआई) ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के दौरान अलग-अलग विषयों पर 144 ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किए, जिससे जीएसआई, विभिन्न राज्य डीजीएमएस और अन्य बाहरी संगठनों के 2,911 प्रतिभागियों को फायदा हुआ। इन ट्रेनिंग पहलों के अलावा, 47 वर्कशॉप/सेमिनार/लेक्चर आयोजित किए गए जिनमें कुल 2,206 लोगों ने भाग लिया। जीएसआई के 175वें वर्ष के समारोहों के हिस्से के रूप में, जीएसआई TI ने "नेक्स्ट-जेन जियोफिजिक्स: 2025-पृथ्वी के छिपे हुए खजानों को खोलना" विषय पर एक सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 326 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी पहल के तहत, जीएसआईटीआई ने तीन अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए, जिसमें 47 देशों के 61 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय पहल राष्ट्रीय कर्मयोगी – बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम के तहत, 50 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1,374 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया

गया। जीएसआईटीआई ने एनपीईए के लिए क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की, जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवधि के दौरान, जीएसआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तहत "भू-वैज्ञानिकों के लिए रिमोट सेंसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग" पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जो वैश्विक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और भू-स्थानिक कौशल को बढ़ावा देता है और इसका उद्घाटन 27.11.2025 को जीएसआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में किया गया। इस प्रोग्राम में मंगोलिया, घाना, इथियोपिया, फिजी, वेनेजुएला, मिस्र, जिम्बाब्वे, तंजानिया, किंगडम ऑफ एस्वातिनी, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, नेपाल सहित 19 देशों के 20 प्रतिभागी शामिल हैं। जीएसआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) से “उत्कृष्ट/बहुत अच्छा” एक्रेडिटेशन हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है – यह 18.11.2025 को मिली अपनी पिछली “अतिउत्तम” रेटिंग से एक अपग्रेड है।

Certificate No.
APP/23/N00097-2

Certificate of Accreditation

The training institute **Geological Survey of India Training Institute** is accredited as **उत्कृष्ट/Very Good** under the Capacity Building Commission's National Standards.

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance with the National Standards. The Accreditation needs to be renewed before the expiry date by the training institution following the due process of assessment.

Accreditation granted on **18/11/2025** is valid until **17/11/2027**

★★★

S.P. Roy
Jt. Secretary
Capacity Building Commission

S. Radha Chauhan
Chairperson
Capacity Building Commission

जीएसआई को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) से "उत्कृष्ट/वेरी गुड" का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है – जो 18.11.2025 को मिली उसकी पिछली "अतिउत्तम" रेटिंग से बेहतर है।

(viii) जनवरी 2025 से नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, कुल 33 राष्ट्रीय स्तर के

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 30 नए समझौता ज्ञापन हैं और 3 समझौता ज्ञापन का विस्तार किया गया है। विभिन्न संगठनों और संस्थानों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में आईआईटी (आईएसएम); एमओआरटीएच, सीईएस एंड एचएस; एनसीएस; भारतीय नौसेना; एनजीआरआई; असम एसडीएमए; जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), एमपी; नीपको; सीजीडब्ल्यूबी; डीडीएमआर, मिजोरम; मेघालय एसडीएमए; डब्ल्यूआरडी, तमिल; डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय; टीडीएमए, त्रिपुरा; एसडीएमए, अरुणाचल प्रदेश; एसडीएमए, प्रबंधन; पीडीईयू; नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए); वीएमएफ प्रौद्योगिकी; आईआईटी बॉम्बे; एनपीसीआईएल; आईआईटीएम, पुणे और आईआईटी केजीपी आदि शामिल हैं।

माननीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, GSI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में नेक्स्ट-जेन जियोफिजिक्स: 2025 कॉन्फ्रेंस में।

(ix) जीएसआई द्वारा बेंगलुरु में डेटा प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन सेल (डीपीआईआईसी) की स्थापना: डीपीआईआईसी की स्थापना जीएसआई द्वारा बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय स्तर के भू-वैज्ञानिक हब के रूप में की जा रही है ताकि कंप्यूटर एडेड क्लासिकल और एडवांस्ड एआई/एमएल/डीएल मेथोडोलॉजी के माध्यम से छिपे हुए और गहरे खनिज भंडार सहित खनिज भंडार की खोज में तेजी लाई जा सके। यह केंद्र बहु-विषयक भू-वैज्ञानिक डेटासेट और तकनीकी रिपोर्ट के व्यवस्थित इनपुट, प्रोसेसिंग, एआई/एमएल/डीएल-सहायता प्राप्त व्याख्या, एकीकरण और प्रसार के लिए वन-स्टॉप सुविधा के रूप में काम करेगा। वर्तमान में, डीपीआर अनुमोदन के अधीन है।

(x) ड्रोन सर्वेक्षण: जीएसआई ने फरवरी 2025 के दौरान दो क्षेत्रों में अपना पहला ड्रोन-आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण शुरू किया: (a) दूदू क्षेत्र, राजस्थान के लडेरा, देवपुरा और सखुन गाँव और (b) मयूरभंज जिला, ओडिशा का मदनसाही-केशरपुर-दुधियासोल क्षेत्र। जीएसआई ने अक्टूबर 2025 में महाकौशल बेल्ट में भी ड्रोन-आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण शुरू किया।

(xi) आंतरिक संसाधन सृजन: इस अवधि के दौरान, विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे प्रायोजित वाणिज्यिक भू-तकनीकी कार्यों; बहु-विषयक और मौलिक अनुसंधान; मानचित्रों, अप्रकाशित रिपोर्टों की बिक्री; नमूनों के विश्लेषण (पेट्रोलॉजिकल/रासायनिक/खनिज भौतिकी/भू-तकनीकी प्रयोगशालाएं), ईपीएएमए अध्ययन और रत्न परीक्षण आदि के माध्यम से कुल 1,83,53,629/- रुपये आंतरिक संसाधन के रूप में और 28,14,972/- रुपये जीएसटी के रूप में एकत्र किए गए हैं।

(xii) हैकाथॉन: जीएसआई ने MoM द्वारा इंडिया-AI मिशन और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मेइटी के सहयोग से आयोजित चल रहे हैकाथॉन "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण" के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। माननीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी और माननीय गोवा के मुख्यमंत्री, डॉ. प्रमोद सावंत ने 13.03.2025 को खान मंत्रालय के सचिव श्री वी.एल. कांता राव की उपस्थिति में

हैकाथॉन 2025 का उद्घाटन किया। जीएसआई की दो टीमों, जिसमें एक ऑल वुमन टीम भी शामिल है, ने जीएसआई, खान मंत्रालय के सहयोग से इंडियाAI मिशन के एप्लीकेशन डेवलपमेंट पिलर के तहत आयोजित इंडिया AI हैकाथॉन 2025 में दो पुरस्कार जीते हैं। विजेताओं की घोषणा 06.11.2025 को की गई और उन्हें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद, मेइटी के सचिव श्री एस. कृष्णन और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया।

(xiii) जीएसआई की स्थापना के 175 वर्ष का उत्सव:

1. 175 वर्ष के उत्सव के अवसर पर, माननीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 4 मार्च, 2025 को, जीएसआई के स्थापना दिवस पर निम्नलिखित मोबाइल ऐप लॉन्च किए:

a. फील्ड डेटा एक्विजिशन (एफडीए)

b. भुविरासत

c. भूस्खलन

2. जीएसआई के 175 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जीएसआई ने 20.11.2025-21.11.2025 को जयपुर में "अतीत को उजागर करना, भविष्य को आकार देना" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित किया। सेमिनार का उद्घाटन माननीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने किया।

3. अपने 175 वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में, जीएसआई ने DGM, निजी अन्वेषण एजेंसियों, एनईए, संस्थान, विश्वविद्यालय और सरकार सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया:

(i) भूविज्ञान में प्रगति: पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित जीवन के लिए नई अंतर्दृष्टि और स्थायी समाधान" (AG-ISM 2025) स्टेट कन्वेंशन सेंटर, शिलांग में 08.04.2025 को।

(ii) नेक्स्ट-जेन जियोफिजिक्स 2025: पृथ्वी के छिपे खजानों को उजागर करना' 09 और 10 जून 2025 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जीएसआईTI), हैदराबाद में।

(iii) महत्वपूर्ण खनिज 7 और 8 अगस्त, 2025 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में।

(xiv) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भू-विरासत स्थल (प्राकृतिक श्रेणी): एक ऐतिहासिक विकास में, भारत के 7 भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों - जिन्हें लोकप्रिय रूप से भू-विरासत स्थलों के रूप में जाना जाता है - को 27 अगस्त 2025 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों (प्राकृतिक श्रेणी) की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये सात स्थल हैं i) नागा हिल ओफियोलाइट नागालैंड, ii) पंचगनी और महाबलेश्वर में दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, iii) सेंट मैरी क्लस्टर की भूवैज्ञानिक विरासत, कर्नाटक, iv) मेघालय युग की गुफाएं, मेघालय, v) एर्रा मट्टी डिब्बलू (लाल रेत के टीले), आंध्र प्रदेश, vi) तिरुमाला पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश, vii) वर्कला क्लिफ, केरल। यह मील का पत्थर जीएसआई और खान मंत्रालय (MoM) द्वारा भू-विरासत संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों से संभव हुआ है।

(xv) जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय, ग्वालियर का उद्घाटन: ग्वालियर में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 15 दिसंबर, 2024 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया, जिनमें श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला और खान राज्य मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, श्री भरत सिंह कुशवाह, सांसद, ग्वालियर शामिल हैं। यह म्यूज़ियम नगर निगम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और नेशनल काउंसिल ऑफ़ साइंस म्यूज़ियम (एनसीएसएम), संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया गया था। इस म्यूज़ियम की स्थापना जीएसआई की भूविज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी और उसके संसाधनों के बारे में जिज्ञासा जगाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

जीएसआई जियोसाइंस म्यूजियम, ग्वालियर का उद्घाटन

(xvi) **जीएसआई की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ** कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों/निकायों और विदेशी एजेंसियों के साथ बातचीत के माध्यम से जारी रहीं, जिसमें सहयोगी कार्यक्रमों और वैज्ञानिक परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी शामिल है, साथ ही सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशालाओं/बैठकों आदि में भी भागीदारी की गई। जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान, जीएसआई के 49 अधिकारियों ने ऐसी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश का प्रमुख पृथ्वी विज्ञान संगठन होने के नाते ज्ञान साझा करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहा है। 2025 के दौरान की गतिविधियों की झलक नीचे दी गई है:

वर्ष (जनवरी-दिसंबर 2025) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थान के साथ हस्ताक्षरित एमओयू/एमओए की एक झलक

नेशनल रिसर्च काउंसिल (सीएनआर-आईआरपीआई), इटली के जियो-हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू और इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट पर वर्चुअल

साइनिंग की झलक।

2. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, खान मंत्रालय, भारत गणराज्य और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ द नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ़ UK, जो यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन का एक हिस्सा है, के बीच एमओयू के विस्तार पर वर्चुअल साइनिंग की झलक।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2025 में शुरू की गई PR पहलों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

• 64वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक 19 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में हुई, जिसमें जीएसआई के 2025-26 के फील्ड सीजन प्रोग्राम पर चर्चा की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया, और आने वाले साल के लिए नई पहलों की योजना बनाई गई।

• जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जीएसआई की समृद्ध भू-वैज्ञानिक विरासत के 175 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 मार्च 2025 को देश भर में अपने सभी कार्यालयों में एक वॉकाथॉन का आयोजन किया।

• माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 4 मार्च 2025 को कोलकाता में जीएसआई के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

• "भू-विज्ञान में प्रगति: पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित जीवन के लिए नई अंतर्दृष्टि और स्थायी समाधान" (एजी-आईएसएम 2025) पर राष्ट्रीय सम्मेलन 8 अप्रैल 2025 को शिलांग में आयोजित किया गया।

• माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 9 जून 2025 को जीएसआई प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में नेक्स्ट-जेन जियोफिजिक्स सेमिनार का उद्घाटन किया।

• जीएसआई ने 18 जुलाई 2025 को कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की पहली वर्षगांठ मनाई।

• जीएसआई के 175 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 2025 को जबलपुर में महत्वपूर्ण खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

• जीएसआई ने रुद्रप्रयाग जिले के लिए ऑपरेशनल भूस्खलन पूर्वानुमान बुलेटिन जारी किया,

• यूनेस्को ने 27 अगस्त 2025 को भारत के सात भू-विरासत स्थलों को अपनी विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल किया, जो भूवैज्ञानिक खजानों की पहचान, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए जीएसआई के राष्ट्रव्यापी जनादेश में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

• जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल, माइनिंग एंड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट (आईएनजीईएमएमईटी), पेरू गणराज्य ने 23.09.2025 को अरेक्विपा, पेरू में क्षेत्रीय भूविज्ञान, खनिज और ऊर्जा संसाधनों, पर्यावरणीय भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक खतरों, प्रयोगशाला अध्ययन और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अध्ययन और ज्ञान विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन और अंतर-संस्थागत सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में जीएसआई के स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान में भाग लिया।

• जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 20-21 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में "अतीत को उजागर करना, भविष्य को आकार देना: जीएसआई के 175 साल" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने किया, और इसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विचारोत्तेजक पूर्ण सत्र और अतिथि व्याख्यान शामिल थे।

64वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग 19 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में हुई, जिसमें जीएसआई के 2025-26 के फील्ड सीज़न प्रोग्राम पर चर्चा की गई और उसे फाइनल किया गया, और आने वाले साल के लिए नई पहल की योजना बनाई गई।

माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 4 मार्च 2025 को कोलकाता में जीएसआई के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

"जियोसाइंस में प्रगति: पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित जीवन के लिए नई समझ और स्थायी समाधान" (AG-ISM 2025) पर राष्ट्रीय सम्मेलन 8 अप्रैल 2025 को शिलांग में आयोजित किया गया था।

माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने 9 जून 2025 को जीएसआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में नेक्स्ट-जेन जियोफिजिक्स सेमिनार का उद्घाटन

किया।

जीएसआई ने 18 जुलाई 2025 को कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर की पहली सालगिरह मनाई।

जीएसआई के 175 साल पूरे होने के मौके पर 7 अगस्त 2025 को जबलपुर में क्रिटिकल मिनरल्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई।

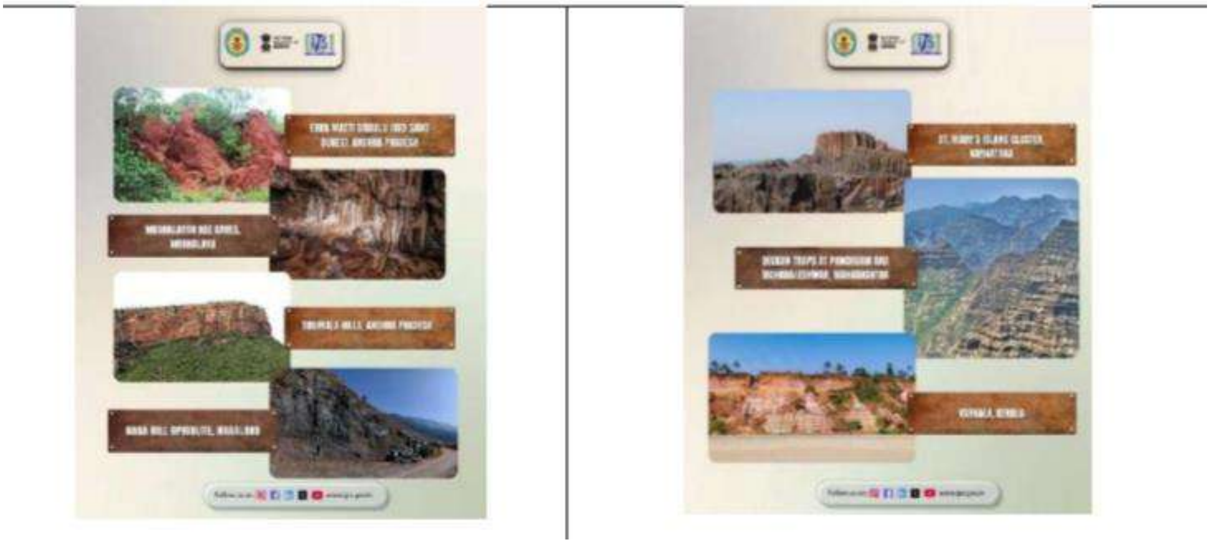

UNESCO ने 27 अगस्त 2025 को भारत की सात जियोहेरिटेज साइट्स को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा, जो जियोलॉजिकल खजानों की पहचान करने, उन्हें डॉक्यूमेंट करने और बचाने के जीएसआई के देश भर में काम में एक बड़ा मील का पत्थर ह

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया और जियोलॉजिकल, माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट (आईएनजीईएमएमईटी), रिपब्लिक ऑफ़ पेरू, ने 23.09.2025 को अरेक्विपा, पेरू में रीजनल जियोलॉजी, मिनरल और एनर्जी रिसोर्स, एनवायर्नमेंटल जियोलॉजी, जियोलॉजिकल खतरे, लैबोरेटरी स्टडी और दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मिलकर पढ़ाई और जानकारी के लेन-देन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग और इंटर-इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए।

श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, ने हैदराबाद में जीएसआई के स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान में भाग लिया।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 20-21 नवंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में "अतीत को उजागर करना, भविष्य को आकार देना: जीएसआई के 175 साल" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने किया और इसमें जाने-माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विचारोत्तेजक पूर्ण सत्र और अतिथि व्याख्यान शामिल थे।

1. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर (जेएनआरडीडीसी), नागपुर

मुख्य गतिविधियाँ:

सेंटर ने छह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए 19 R&D प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। जेएनआरडीडीसी को लेबोरेटरी रिकग्निशन स्कीम (LRS) के तहत BIS-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिससे संस्थान आने वाली क्यूसीओ आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता प्राप्त परीक्षण सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

पिछले साल केंद्रीय बजट घोषणा के साथ एक बड़ा राष्ट्रीय मील का पत्थर स्थापित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना की गई। यह मिशन– जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29.01.2025 को ₹16,300 करोड़ के परिव्यय और PSUs द्वारा ₹18,000 करोड़ के अपेक्षित निवेश के साथ मंजूरी दी–इसका उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक एक लचीली महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। जेएनआरडीडीसी महत्वपूर्ण खनिज रिकवरी के लिए पायलट प्लांट स्थापित करके, REE और महत्वपूर्ण खनिज लक्षण वर्णन, और आईबीएम और जीएसआई को रणनीतिक सहायता प्रदान करके एनसीएमएम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह सेंटर दो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, सीओईs यानी आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर के लिए एक "स्पोक" के रूप में भी काम कर रहा है।

खान मंत्रालय (MoM) के लिए मुख्य कार्य –

• मेटल रीसाइक्लिंग अथॉरिटी (एमआरए) – "राष्ट्रीय गैर-लौह धातु स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क 2020" में निर्धारित एमआरए के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना।

• एल्युमिनियम स्क्रैप के लिए ईपीआर

• S&T- PRISM कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप और एमएसएमईs को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी।

• महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग पर प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)।

• खान मंत्रालय की योजना जिसका शीर्षक है "ओवरबर्डन / टेलिंग्स / फ्लाई ऐश / रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए पायलट प्रोजेक्ट" के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी। महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग पर प्रोत्साहन योजना के लिए जेएनआरडीडीसी को PMA के रूप में

29.01.2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना की गई है, जिसमें कई प्रमुख घटक शामिल हैं जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की खोज और नीलामी बढ़ाना, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण, रीसाइक्लिंग, कौशल विकास, अनुसंधान और विकास, आदि। विशेष रूप से, एनसीएमएम के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए एक प्रोत्साहन योजना, जिसमें प्रोत्साहन की राशि ₹1,500 करोड़ तय की गई है, जेएनआरडीडीसी को परियोजना निगरानी एजेंसी (PMA) के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह योजना उद्योग को देश में महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी ताकि रीसाइक्लिंग के माध्यम से

माध्यमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग किया जा सके और उनका उत्पादन किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य बढ़ी हुई घरेलू क्षमता और आयात पर निर्भरता कम करके महत्वपूर्ण खनिजों में आर्थिक लचीलापन लाना है; और फीडस्टॉक की बढ़ती उपलब्धता के बीच रीसाइक्लिंग क्षमता की कमी को दूर करना है। यह योजना 2 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई थी।

स्टार्टअप और एमएसएमईs के लिए S&T- PRISM योजना का कार्यान्वयन

PRISM 4.0 के तहत खान मंत्रालय ने निम्नलिखित छह एजेंसियों को फंड स्वीकृत किया: (i) स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रीज, मैंगलोर, कर्नाटक (ii)K2BJN इंडस्ट्रीज LLP; श्रीरंगम, तमिलनाडु (iii)फोंसमेंट मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र(iv) NiLiCo ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड; बेंगलुरु (v) भाग्यनगर मैग्नीशियम प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना और (vi) एगियन एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत, हरियाणा। जेएनआरडीडीसी ने फंड जारी करने से पहले इन संस्थाओं का तकनीकी और वित्तीय उचित परिश्रम सफलतापूर्वक किया। फंडिंग को अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त तरीके से नवीन प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/सेवाओं के विकास और व्यावसायीकरण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। जेएनआरडीडीसी ने तकनीकी मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में जेएनआरडीडीसी के निदेशक के साथ परियोजना के अंतिम पुरस्कार तक प्रस्तावों का मूल्यांकन करके कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्टार्टअप और एमएसएमई के माध्यम से नवाचार-संचालित विकास पर मंत्रालय के फोकस को रेखांकित करता है। पेटेंट: "मशीनिंग स्वार्फ से पायलट स्केल एक्सट्रूज़न बिलेट्स और एक्सट्रूडेट्स बनाने की एक प्रक्रिया"। आवेदन संख्या 202521042386, दिनांक: 01-05-2025 (दाखिल)

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

i. एल्युमिनियम स्मेल्टर से उत्पन्न खतरनाक एसपीएल (पहला कट) के सुरक्षित संचालन, उपचार और विषहरण के लिए एसपीएल विषहरण प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया का हस्तांतरण, विशेष रूप से ओडिशा राज्य में और इसके आगे उपयोग के लिए निम्नलिखित एजेंसियों को:

- आर्केन मिनरल्स ट्रेडिंग, एएमटी, कटक
- A3 मिनरल्स एंड मेटल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कटक
- इवॉल्व कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर

ii. "एल्युमिनियम मशीनिंग स्वार्फ से पायलट-स्केल एक्सट्रूज़न बिलेट्स और एक्सट्रूडेट्स बनाने की प्रक्रिया" की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण:-

- ग्रीनमेटलिक्स, कलमेश्वर, नागपुर

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रीसाइक्लिंग संवर्धन प्रभाग की स्थापना

राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क 2020 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं।

• जेएनआरडीडीसी नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग (डेमोंस्ट्रेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट यूनिट) के लिए एक स्टेट ऑफ़ आर्ट सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बना रहा है।

• माननीय कोयला और खनन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा एक नेशनल डेटाबेस और सुविधा प्लेटफॉर्म के तौर पर नॉन-फेरस मेटल रीसाइक्लिंग वेबसाइट और स्टेकहोल्डर्स पोर्टल (nfmrecycling.जेएनआरडीडीसी.gov.in) लॉन्च किया गया।

- 600 से ज्यादा रीसाइक्लिंग उद्योग पंजीकृत किए गए

- जेएनआरडीडीसी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा के लिए खान मंत्रालय की देखरेख में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन आयोजित किए गए:
    - स्क्रैप रीसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स के लिए प्रोसेस स्टैंडर्ड
    - रीसाइक्लिंग यूनिट्स के लिए न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें तय करना
    - एमओईएफसीसी और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर और यूनिट्स की रैंकिंग और मूल्यांकन के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करना

• पीडब्ल्यूसी के माध्यम से भारत में नॉन-फेरस मेटल्स (एनएफएम) के लिए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए विजन डॉक्यूमेंट: पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार की गई शुरुआती रिपोर्ट और मॉड्यूल 1 के विकास में सहायता के लिए स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की गई। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के ड्राफ्ट वर्तमान में जेएनआरडीडीसी द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

इस साल, जेएनआरडीडीसी ने महत्वपूर्ण सहयोग के लिए बातचीत शुरू करके अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया, जिससे भारत की महत्वपूर्ण खनिजों, रीसाइक्लिंग और उन्नत सामग्रियों में क्षमताओं को मजबूती मिली।

• ब्लैकस्मिथ इंस्टीट्यूट dba प्योर अर्थ लैब, न्यूयॉर्क, USA: रीसायकल किए गए एल्यूमीनियम कुकवेयर में लेड संदूषण के लिए चल रही परियोजना – स्रोतों की पहचान करना और लेड हटाने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना।

• मा'आदेन बॉक्साइट एंड एल्यूमिना कंपनी, सऊदी अरब: बॉक्साइट प्रोसेसिंग में धूल दमन रसायनों को मिलाने के प्रभाव पर अध्ययन के लिए परियोजना शुरू की गई।

• JSC टाइटेनियम इंस्टीट्यूट, यूक्रेन – बेयर लिकर से गैलियम निष्कर्षण (1000 लीटर क्षमता) के लिए स्वदेशीकरण और पायलट-स्केल प्रदर्शन संयंत्र के लिए सहयोग, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पायलट संयंत्र इंजीनियरिंग शामिल है।

• डाइकी एल्यूमीनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, जापान – एल्यूमीनियम रीसाइक्लिंग, मिश्र धातु विकास (ADC12/LM24), और सर्कुलरिटी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर तकनीकी सहयोग, जो गैर-लौह रीसाइक्लिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र में योगदान देगा। माध्यमिक इस्पात निर्माण के लिए सिंथेटिक स्लैग तैयार करने में एल्यूमीनियम ड्रॉस के उपयोग के लिए चल रही परियोजना।

•रुसल और रूसी संस्थान (MiSIS) – रेड मड प्रोसेसिंग, लौह पुनर्प्राप्ति, एल्यूमिना शोधन सुधार, और स्थायी धातुकर्म प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान का आदान-प्रदान।

• अरेबियन एक्सट्रूज़न फैक्ट्री L.L.C, उम्म अल क्वैन, U.A.E. – जेएनआरडीडीसी के पास एनएबीएल ISO-17034:2016 मान्यता है और उसने प्रमाणित संदर्भ सामग्री, सीआरएम निर्यात की हैं जिनका उपयोग अंशांकन और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए मानकों के रूप में किया जाएगा।

पुरस्कार / मान्यता

जेएनआरडीडीसी को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2025 के लिए देश के शीर्ष पांच अभिनव अनुसंधान संस्थानों में मान्यता दी गई है। डॉ. अनुपम अग्निहोत्री, निदेशक जेएनआरडीडीसी को सीआईआई इनोवेशन अवार्ड समारोह 2025 के दौरान औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया।

श्री सतीश दुबे, माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री द्वारा जेएनआरडीडीसी की समीक्षा

श्री सतीश दुबे जी, माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री, भारत सरकार, और राज्यसभा सदस्य, ने 27 नवंबर 2025 को जेएनआरडीडीसी का दौरा किया ताकि केंद्र के चल रहे R&D कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सके। इस दौरे के दौरान, उन्होंने नई एक्सआरएफ प्रयोगशाला का उद्घाटन किया - यह एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है जो जेएनआरडीडीसी की विश्लेषणात्मक और परीक्षण क्षमताओं को काफी मजबूत करता है। यह प्रयोगशाला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई), इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आईबीएम), ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (ओएमसी), और विभिन्न अन्य सार्वजनिक और निजी एजेंसियों जैसे प्रमुख हितधारकों की सेवा करेगी। यह महत्वपूर्ण खनिज मूल्यांकन के लिए विशेष महत्व रखती है, जो भारत के बढ़ते खनिज क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फ्लोरीन, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य रणनीतिक या उच्च-मूल्य वाले खनिजों के विश्लेषण के लिए बेहतर क्षमताएं प्रदान करती है।

विशेष अभियान 5.0

जेएनआरडीडीसी ने खान मंत्रालय के विशेष अभियान 5.0 के तहत देशव्यापी घरेलू ई-कचरा रीसाइक्लिंग पहल का नेतृत्व किया। देश भर में 58 स्थानों पर लागू इस अभियान ने एटीटीईआरओ रीसाइक्लिंग और एमआरएI जैसे अधिकृत रीसाइक्लर्स के माध्यम से सफलतापूर्वक 9.02 टन ई-कचरा इकट्ठा किया, जिसमें ₹11 लाख से ज़्यादा का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य ज़िम्मेदार ई-कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कर्मचारियों और भागीदार संगठनों के बीच स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में अग्रणी भूमिका

1. जेएनआरडीडीसी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की एक कार्यान्वयन शाखा के रूप में उभरा है। रणनीतिक तत्वों को पुनर्प्राप्त करने और औद्योगिक कचरे को उच्च-मूल्य वाले उत्पादों में बदलने के लिए पायलट और प्रदर्शन संयंत्रों की एक श्रृंखला की कल्पना की गई है, डिज़ाइन किया गया है और स्थापित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का सामूहिक लक्ष्य वैश्विक स्वच्छ-ऊर्जा और चक्रीय-अर्थव्यवस्था मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

1.1 रणनीतिक तत्वों के लिए पायलट और प्रदर्शन संयंत्र

• बायर लिकर से गैलियम निष्कर्षण: JSC टाइटेनियम इंस्टीट्यूट (यूक्रेन) के सहयोग से, जेएनआरडीडीसी में 1,000-लीटर का एक पायलट-सह-प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है – यह भारत की ऐसी पहली सुविधा है। यह सेमीकंडक्टर, एलईडी और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए 4N-शुद्धता वाला गैलियम का उत्पादन करेगा।

• रेड मड और टाइटेनियम अवशेषों से स्कैंडियम रिकवरी (बातचीत का अंतिम चरण):रुसल (रूस) और भारतीय भागीदारों के सहयोग से उनके निर्देशन में शुरू की गई यह परियोजना एयरोस्पेस और ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण स्कैंडियम की रिकवरी के लिए भारत के विशाल रेड-मड संसाधनों का उपयोग करेगी।

• फार्मास्युटिकल कचरे से निकेल रिकवरी (जारी): यह परियोजना फार्मास्युटिकल खर्च किए गए कीचड़ से निकेल और कोबाल्ट की रिकवरी को लक्षित करती है, जिससे भारत को ईवी और बैटरी-विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक सामग्री सुरक्षित करने में मदद मिलती है।

• सेकेंडरी स्टील उद्योग से निकेल और क्रोमियम रिकवरी (जारी): यह परियोजना सेकेंडरी स्टील रीसाइक्लिंग उद्योगों से निकेल की रिकवरी को लक्षित करती है, जिससे भारत को आवश्यक सामग्री सुरक्षित करने में मदद मिलती है।

• टेंटलम और नायोबियम की टिन स्लैग से रिकवरी (जारी): जेएनआरडीडीसी ने बीएचयू के सहयोग से छत्तीसगढ़ में टिन-स्लैग जमाव से नायोबियम और टेंटलम को रिकवर करने के लिए ट्राइज़ीन-डेरिव्ड g-C□N□-आधारित सेपरेशन का उपयोग करके एक नई प्रक्रिया शुरू की है। ये धातुएं हाई-टेम्परेचर अलॉय, कैपेसिटर और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• TiO_2 पिगमेंट उद्योग के कचरे से गैलियम की रिकवरी (जारी): सीएसआईआर-एनआईआईएसटी के सहयोग से एक नई परियोजना का लक्ष्य भारत के रणनीतिक उद्योगों का समर्थन करने के लिए पेंट/पिगमेंट उद्योग के कचरे से गैलियम को रिकवर करने के लिए एक कुशल प्रक्रिया विकसित करना है।

• चट्टान की धूल (ग्रेनाइटिक नीस) से पोटाश की रिकवरी (जारी): सीएसआईआर-एनआईआईएसटी के सहयोग से एक नई परियोजना का लक्ष्य भारत के रणनीतिक उद्योगों का समर्थन करने के लिए चट्टान की धूल (ग्रेनाइटिक) से पोटाश को रिकवर करने के लिए एक कुशल प्रक्रिया विकसित करना है।

1.2 कचरे से धन और सर्कुलर-इकोनॉमी प्रदर्शन परियोजनाएं

• रेड मड से ईंटें (नाल्को दमनजोड़ी) (दिसंबर 2025 में शुरू होगी): M/s मनीश्री सिरेमिक्स एंड रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक डेमो-कम-पायलट सुविधा स्थापित की जा रही है ताकि रेड-मड को निर्माण ईंटों में बदला जा सके, जिससे इस प्रमुख कचरे का बड़े पैमाने पर उपयोग संभव हो सके। • पेंट उद्योग के लिए रेड मड से पिगमेंट: घरेलू पेंट निर्माताओं की उद्योग भागीदारों के रूप में सक्रिय भागीदारी के साथ, रेड-मड को पेंट में उपयोग के लिए पिगमेंट-ग्रेड सामग्री में बदलने के लिए एक और पायलट-स्केल सुविधा विकसित की जा रही है।

• एक्सट्रूज़न प्लांट के कचरे से उच्च-शुद्धता 3N एल्यूमिना और ज़ियोलाइट: एल्यूमीनियम-एक्सट्रूज़न कीचड़ को 3N-ग्रेड एल्यूमिना पाउडर और ज़ियोलाइट (डिटर्जेंट और उत्प्रेरक उद्योगों के लिए) में बदलने के लिए एक पायलट-स्केल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना औद्योगिक कचरे में स्थायी मूल्यवर्धन का एक उदाहरण है।

• रीसाइक्लिंग उद्योग के लिए नमक की गंदगी से पुन: प्रयोज्य फ्लक्स: नमक की गंदगी को पुन: प्रयोज्य फ्लक्सिंग सामग्री में बदलने के लिए 100 किलोग्राम की पायलट-स्केल सुविधा शुरू की जा रही है, जिससे एल्यूमीनियम रीसाइक्लिंग में शून्य-कचरा प्रक्रिया प्राप्त होगी। • मल्टी-लेयर पैकेजिंग मटीरियल (MLP) की रीसाइक्लिंग: MLP कचरे में प्लास्टिक, मेटल और पॉलीमर को मैकेनिकल और केमिकल तरीके से अलग करने के लिए एक 1 TPD पायलट प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि रीसाइकिल करने लायक और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट बनाए जा सकें।

M. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) और काम के मुख्य क्षेत्र

एनआईआरएम पिछले 35 सालों से देश की सेवा कर रहा है, जो साइट कैरेक्टराइजेशन, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के डिजाइन और खुदाई, रॉक मास की एडवांस्ड मॉनिटरिंग और टेस्टिंग सेवाओं के ज़रिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समाधान देने के लिए इंडस्ट्री-स्पेसिफिक अप्लाइड रिसर्च एक्टिविटीज़ को मिलाता है।

एनआईआरएम की गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र हैं:

1. साइट कैरेक्टराइजेशन - एनआईआरएम में इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल, सीस्मोटेक्टोनिक, इंजीनियरिंग जियोफिजिकल, इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजिकल के आधार पर माइनिंग, टनल, डैम, पावर प्लांट और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विभिन्न प्रोजेक्ट साइट्स को कैरेक्टराइज करने की क्षमता है।
2. डिजाइन और खुदाई - सतह और भूमिगत खदान डिजाइन, खुदाई इंजीनियरिंग, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, न्यूमेरिकल मॉडलिंग, पहाड़ी ढलानों का डिजाइन
3. एडवांस्ड मॉनिटरिंग - माइक्रोसिस्मिक मॉनिटरिंग, ढलान स्थिरता मॉनिटरिंग, पारंपरिक इंस्ट्रूमेंटेशन मॉनिटरिंग

4. टेस्टिंग सेवाएं – चट्टान के नमूनों और वायर रस्सियों का प्रयोगशाला परीक्षण और एनडीटी तकनीक का उपयोग करके विभिन्न खनन एक्सेसरीज़ का इन-सीटू परीक्षण

एनआईआरएम प्रदर्शन और अनुमान

01 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 के दौरान पूरे किए गए प्रोजेक्ट: 28 एनआईआरएम में काम का कैशफ्लो इंडस्ट्री की ज़रूरतों और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चल रहे प्रोजेक्ट की अवधि पर निर्भर करता है, जो हमेशा बदलता रहता है। इस अवधि के दौरान, एनआईआरएम ने सालाना कैश फ्लो लक्ष्य का 75% हासिल किया है।

एनआईआरएम अपने वर्कफोर्स और संसाधनों के ज़रिए इंडस्ट्री की मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बेहतर वैज्ञानिक उपकरण और अपग्रेडेड सुविधाएं शामिल हैं। चूंकि संस्थान प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई के आधार पर आत्मनिर्भरता मॉडल अपना रहा है, इसलिए वित्तीय स्थिरता के लिए, चुनौतीपूर्ण और बदलते इंडस्ट्री ट्रेंड के तहत उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएं जारी रखने के लिए, एनआईआरएम को कुशल युवा मानव संसाधन, मजबूत प्रशासनिक ढांचा और स्थिरता और विकास के लिए स्वस्थ वित्तीय खर्च के मामले में मजबूत समर्थन की आवश्यकता है। एनआईआरएम प्रभावी योजना और खान मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन से अपने वर्कफोर्स को मजबूत करने और अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। इस समर्थन से एनआईआरएम विभिन्न इंडस्ट्री और वैश्विक संगठनों तक पहुँचकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपनी गतिविधियों को तेज़ करने की उम्मीद करता है।

इंडस्ट्री की मांगों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक वर्कफोर्स के लिए इंडस्ट्री ट्रेंड के कौशल और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हैं। संस्थान के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक कर्मचारी काम से संबंधित पूछताछ के माध्यम से दी गई चुनौतियों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने और साइट-विशिष्ट कुशल समाधान प्रदान करने के लिए स्व-प्रेरित हैं। एनआईआरएम के वैज्ञानिक बीआईएस, आईएसआरएम, आईएसईजी, एमईएआई, केएसडीसी, केएसडीएमए, आईजीएस, आईजीयू, आईएसईटी, और आईएसआरएमटीटी के लिए अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के सदस्य रहे हैं। शिक्षाविदों से युवा दिमाग और उभरते इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को शामिल करने के लिए, छात्रों को समय-समय पर शोध प्रबंध और इंटर्नशिप कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।

समझौता ज्ञापन

एनआईआरएम ने अब तक जीएसआई, एमओआरटीएच,, एनएचआईडीसीएल, एनपीसीआईएल, एससीटी (एनएसडब्ल्यू) और विभिन्न खनन प्रौद्योगिकी और सेवा कंपनियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनआईआरएम की उपलब्धियां: माइनिंग और टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा, इनोवेशन और विश्वसनीयता को आगे बढ़ाना

रेलवे सुरंगों के लिए इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक जांच

(i) इंजीनियरिंग भूविज्ञान वैज्ञानिकों की टीम ने महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1, 2, 3, और 4 में ऑनसाइट इमरजेंसी सपोर्ट सेंटर (OESC) के लिए नींव के मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए रीमैपिंग (1:100 स्केल पर) किया।

चट्टान समूह में सभी महत्वपूर्ण दरारों की मैपिंग, बेसाल्टिक चट्टान समूहों के लिए RMR का मूल्यांकन, नींव के उपचार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों का कारण बना। यहां OSEC बिल्डिंग की नींव का बर्ड्स-आई व्यू देखें, जियो-मैपिंग के लिए ग्रिड चिह्नित किए जा रहे हैं।

(ii) यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए भविष्य की रेल कनेक्टिविटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) द्वारा धनसिरी से ज़ुब्ज़ा के बीच एक नई रेलवे ब्रॉड गेज लाइन बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में कुल 14 सुरंगों का निर्माण शामिल है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) मैनेजमेंट ने नागालैंड में दीमापुर-कोहिमा रेलवे लाइन में बन रही रेलवे सुरंगों (सुरंग संख्या 1, 4, 6, 7 और 10) के डिज़ाइन रिव्यू और ऑडिट के लिए एनआईआरएम से संपर्क किया। एनआईआरएम के वैज्ञानिकों ने साइट पर काम किया और सुरक्षा और टिकाऊपन के लिए खुदाई के तरीके की सिफारिश करते हुए एक व्यापक इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक जांच रिपोर्ट प्रदान की।

(iii) नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिरिबाम-इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है और जटिल भूवैज्ञानिक स्थितियों में ढलान स्थिरता और सुरंग संरेखण सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर महत्वपूर्ण भू-तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों का समाधान एनआईआरएम के वैज्ञानिकों द्वारा साइट पर किए गए विस्तृत अध्ययन से किया गया, विशेष रूप से सुरंग संख्या 8 के पोर्टल-1 (चेनेज किमी 34/111), तुपुल यार्ड (चेनेज किमी 96.040 से किमी 97.958), और नोनी यार्ड (चेनेज किमी 87.400 से 88.502) पर। कमजोर/जोखिम भरे क्षेत्रों की पहचान के लिए स्थिरता विश्लेषण किया गया, परिवहन के लिए सुरक्षित सुरंगों को सक्षम करने के लिए शमन उपायों की सिफारिश की गई।

(iv) एनआईआरएम ने कुरनूल, आंध्र प्रदेश में निर्माण चरण के दौरान 1.2 किमी लंबी जुड़वां सुरंगों (NH150A) के लिए इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक जांच और मैपिंग की। सुरंग का आकार आधा अर्ध-वृत्ताकार है, और अधिकतम खोदी गई चौड़ाई और ऊंचाई 18.50 मीटर और 10.95 मीटर है। चूंकि यह क्षेत्र कुरनूल और कडप्पा संरचनाओं के बीच संपर्क के पास स्थित है। मिश्रित ज़मीनी स्थितियों और विभिन्न लिथो-इकाइयों की भौतिक, यांत्रिक और

संरचनात्मक विशेषताओं में व्यापक भिन्नताओं के कारण, सुरंग की परिधि के साथ सुरंग माध्यम का विषम और गैर-समान व्यवहार देखा जाता है। इस काम ने सुरंग निर्माण कार्य को खुदाई के दौरान साइट पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद की और प्रगति के लिए समय पर समाधान प्रदान किया।

सुरंगों के लिए सतह के नीचे खुदाई के लिए न्यूमेरिकल मॉडलिंग और एनालिसिस

(i) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एम्सीपी) की ओपन पिट खदान अपनी आखिरी पिट लिमिट तक पहुँच गई है। इसके अलावा, खदान स्थल पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप स्ट्रेस सिस्टम का पुनर्वितरण हुआ है और नियोजित बेंच नष्ट हो गए हैं।

एनआईआरएम के वैज्ञानिकों ने भूवैज्ञानिक और खदान विकास के विवरण पर काम किया और खदान के 3D भूवैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए, जिससे फुटवॉल ड्राइव, सब-फुटवॉल ड्राइव, अयस्क ड्राइव और जंक्शन जैसी जगहों पर खुदाई के दौरान भूमिगत खदान की स्थिरता के बारे में जानकारी मिली।

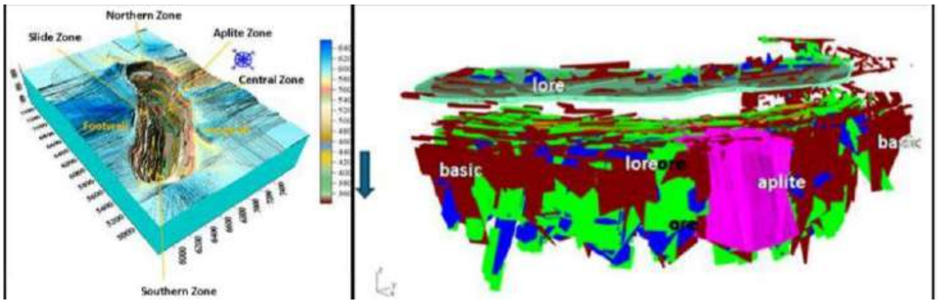

खुले गड्ढे का डिजिटल एलिवेशन मॉडल (बाएं) और गड्ढे का 3D जियोलॉजिकल मॉडल (दाएं)

(ii) जीएमडीसी का काडीपानी ओपनकास्ट फ्लूओरस्पार और काडीपानी विस्तार प्रोजेक्ट, जो 252 हेक्टेयर में फैला हुआ है, गुजरात में अपने फ्लूओरस्पार भंडार के लिए महत्वपूर्ण खदानों में से एक है। प्रोसेस्ड फ्लूओरस्पार हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, रेफ्रिजरेंट गैसों के निर्माण के लिए और मेटलर्जिकल उद्योगों में फ्लक्स के रूप में एक प्रमुख कच्चा माल है। एनआईआरएम ने 3D न्यूमेरिकल मॉडलिंग, काइनेमेटिक एनालिसिस और अल्टीमेट पिट स्लोप और उसके डिज़ाइन के स्टेबिलिटी एनालिसिस के माध्यम से महत्वपूर्ण खदान मापदंडों पर काम किया। एनआईआरएम के काम से खदानों में सुरक्षा और लगातार उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिली।

भूमिगत खदानों में भूकंपीय खतरे की माइक्रोसिस्मिक निगरानी

(i) एनआईआरएम के वैज्ञानिकों ने भूमिगत खदानों में होने वाली भूकंपीय गतिविधि के विश्लेषण पर मार्गदर्शन देकर सहायता प्रदान की और रामपुर औघचा भूमिगत खदानों में रॉकबर्स्ट और असामान्य तनाव क्षेत्रों के रूप में बड़े व्यवधानों के भूकंपीय खतरे और संभावना का लगातार मूल्यांकन किया। 1000 मीटर की गहराई पर काम करने वाली गहरी खदान के लिए यह रियल-टाइम निगरानी, जिसमें खनन-प्रेरित भूकंपीय गतिविधि बढ़ गई थी, ने स्टॉप डिज़ाइन और कामकाज के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान को परिष्कृत किया गया जिससे भूमिगत खतरे का बेहतर प्रबंधन और लगातार उत्पादन हुआ।

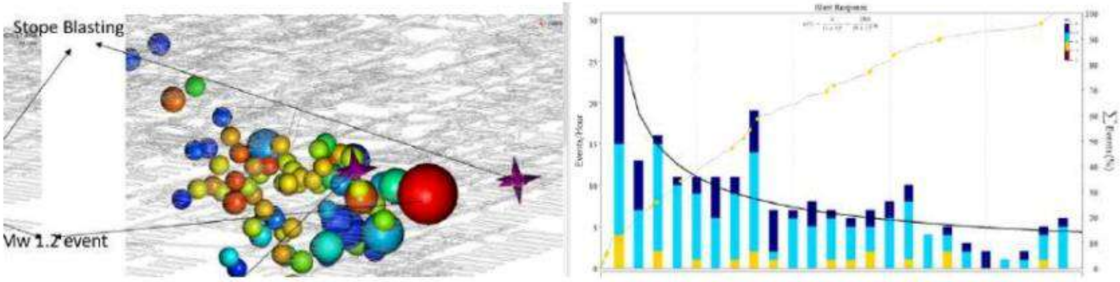

एनपीसीआईएल कैगा साइट पर टरबाइन की अतिरिक्त यूनिट्स के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग

(i) एनआईआरएम ने कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करके कैगा में एनपीसीआईएल पावर प्लांट के इलाके में ज़रूरी खुदाई के लिए तकनीकी गाइडेंस दी। अतिरिक्त टरबाइन बिल्डिंग यूनिट

5 और 6 की जगहों पर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तरीकों से कठोर चट्टान की खुदाई करनी थी, जो यूनिट 1 से 4 के स्ट्रक्चर के करीब हैं। ज़मीन के कंपन, हवा के ओवरप्रेशर और खास साइट प्रेडिक्टर इक्वेशन के अध्ययन के आधार पर, अलग-अलग स्ट्रक्चर के लिए सुरक्षित खुदाई डिज़ाइन की गई। अपनाए गए ब्लास्ट डिज़ाइन ने यह पक्का किया कि ज़रूरी स्ट्रक्चर के पास मॉनिटर किए गए ज़मीन के कंपन और हवा के ओवरप्रेशर का लेवल तय सीमा के अंदर थे। कुल मिलाकर 1400 से ज़्यादा ब्लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की चालू यूनिट के पास, 20m से 300m की दूरी पर किए गए।

भूस्खलन स्थल की बहाली और आगे के बचाव के सुझाव

एनआईआरएम के वैज्ञानिकों ने NH-66 के हाईवे सेक्शन CH. 148.000 (14.603554°N / 74.371219°E) पर भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में विस्तृत अध्ययन किया, जो शिरूर गांव, अंकोला तालुक, उत्तर कन्नड़ जिले, कर्नाटक में है। कमजोर/जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई और आगे भूस्खलन को रोकने के लिए बचाव उपायों के लिए सुझाव बहुत कम समय में दिए गए। इससे हाईवे अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए हाईवे को बहाल करने में मदद मिली। यह हाईवे की ढलानों के हाल के इतिहास में सबसे खराब भूस्खलन की घटनाओं में से एक थी।

चेन्नई एयरपोर्ट पर एनआईआरएम खुदाई डिज़ाइन

चेन्नई एयरपोर्ट पर ऑपरेटिंग टर्मिनल बिल्डिंग, फ्लाइट पार्किंग एरिया के पास टर्मिनल 3 के विस्तार के लिए, खुदाई की गतिविधियों के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण ब्लास्टिंग की गई। एनआईआरएम की कुशलता के कारण फील्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौजूदा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पास किए गए सभी ब्लास्ट सुरक्षित थे और खुदाई के काम से अप्रभावित रहे।

एनआईआरएम भूभौतिकीय जांच वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, नवी मुंबई के लिए चट्टान संसाधनों की मात्रा निर्धारित करती है।

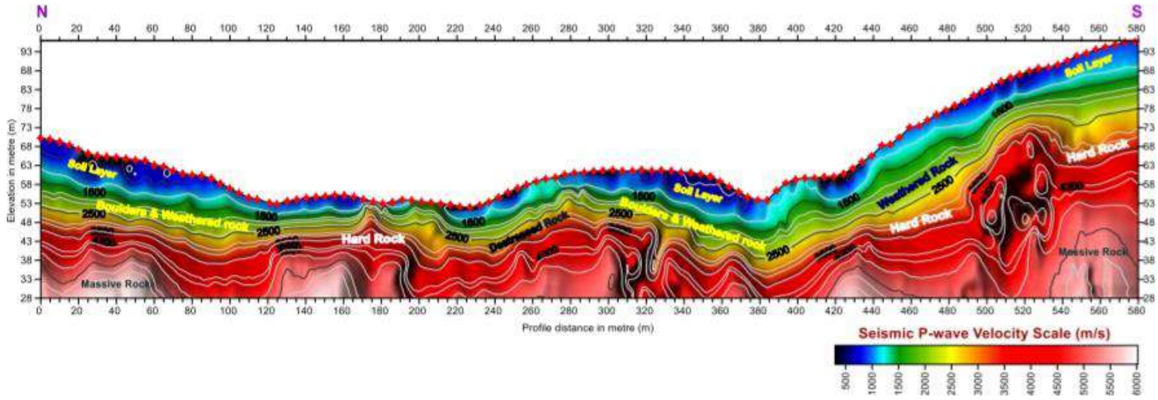

अनुमान के अनुसार, प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी मात्रा 65 MMt से ज़्यादा है। वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट, नवी मुंबई, नवी मुंबई के लिए आर्मर चट्टानों और एग्रीगेट्स की ज़रूरत के लिए, पालघर ज़िले में तीन खदान स्थलों से, सतह के नीचे चट्टानों की स्थिति की जियोफिजिकल इमेजिंग संसाधन के 40 मीटर गहराई तक के बेहतर इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे अनुमानित खराब चट्टान/पत्थर/तनाव रहित चट्टान की परत, और निर्माण के लिए उपयोगी कठोर चट्टान का पता चला।

सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (2000 MW) NM2307C के कंक्रीट बांध के बाएं किनारे की ढलान/एबटमेंट के लिए ढलान स्थिरता अध्ययन

एनएचपीसी लिमिटेड ने ढलानों के व्यापक विश्लेषण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) से संपर्क किया, और कंटीन्यूम और डिस्कंटीन्यूम दोनों विश्लेषणों का अनुरोध किया।

ढलान स्थिरता विश्लेषण FLAC3D का उपयोग करके कंटीन्यूम मॉडलिंग और 3DEC सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिस्कंटीन्यूम मॉडलिंग के माध्यम से किया गया। मॉडलिंग दृष्टिकोण बाएं किनारे की ढलानों की स्थिरता स्थितियों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संयुक्त सेट और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित था। एनआईआरएम ने संख्यात्मक मॉडलिंग परिणामों के आधार पर स्थिरीकरण उपायों की सिफारिश की है। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2025 में जमा की गई।

फुएंटसांगछू-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भूटान के पावरहाउस कॉम्प्लेक्स के इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा का विश्लेषण (जनवरी 2025 से फरवरी 2026) (NM2404C)

भूटान में पुनात्सांगछू-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में एनआईआरएम द्वारा MPBX, एंकर लोड सेल, इंस्ट्रूमेंटेड रॉक बोल्ट, पीज़ोमीटर, स्ट्रेन गेज, और प्रमुख भूमिगत गुफाओं में स्थापित बोरहोल स्ट्रेस मीटर के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन किया गया था। एनआईआरएम डेटा की निगरानी कर रहा है, और डेटा का विश्लेषण कर रहा है और समय-समय पर अधिकांश स्थानों पर विकृतियों और भार को स्थिर करने के उपायों की सिफारिश की है। एनआईआरएम वैज्ञानिक विश्लेषण और परिणाम को मान्य करने के लिए निरीक्षण करते हैं।

उद्योग के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम

(i) थिम्फू, भूटान में ड्रुक ग्रीन कर्मचारी। HR-2501

एनआईआरएम ने थिम्फू, भूटान में ड्रुक ग्रीन कर्मचारियों (20 अधिकारियों) के लिए RocScience सॉफ्टवेयर पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम 23-06-2025 से 27-06-2025 तक आयोजित किया गया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम में Rocscience सॉफ्टवेयर, जैसे RS2, RS3,

Dips, Unwedge, Slide2D और Slide 3D शामिल थे।

(ii) न्यूमेरिकल मॉडलिंग डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक इटैस्का मिनियापोलिस ऑफिस,मिनेसोटा, USA में इटैस्का कोड्स पर 'एडवांस्ड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम' में भाग लिया। इटैस्का द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम3D मॉडलिंग के मौलिक और उन्नत दोनों पहलुओं की व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था,जिससे भाग लेने वाले वैज्ञानिकों को इटैस्का के 3DEC और FLAC3D कोड का उपयोग करके रॉक मैकेनिक्स और रॉक इंजीनियरिंग में जटिल 3D स्ट्रेस विश्लेषण समस्याओं को हल करने की विशेषज्ञता मिल सके। इस प्रोग्राम में रॉकमैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मॉडलिंग में IMAT सॉफ्टवेयर सहित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। वैज्ञानिकों नेMINEDW इटैस्का सॉफ्टवेयर से संबंधित इटैस्का डेनवर ऑफिस और कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस,डेनवर का दौरा चर्चा और भविष्य के लिए किया।

एनआईआरएम के वैज्ञानिक इटैस्का ऑफिस, मिनियापोलिस में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान इटैस्का अधिकारियों के साथ बातचीत/चर्चा कर रहे हैं एनआईआरएम वैज्ञानिक प्रकाशन: उद्योगों को समय पर समाधान प्रदान करने के अलावा, एनआईआरएम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, पीयर-रिव्यूड पत्रिकाओं और अन्य तकनीकी प्रकाशनों के माध्यम से 12 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए हैं।

आईआईटीF2025 में एनआईआरएम की भागीदारी और जागरूकता गतिविधियाँ

14-27 नवंबर, 2025 के दौरान, एनआईआरएम ने आईआईटीF2025 में खान मंत्रालय के पवेलियन के हिस्से के रूप में प्रगति मैदान नई दिल्ली में वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया ताकि विभिन्न खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को समाधान प्रदान करने में अपनी गतिविधियोंऔर क्षमताओं को प्रदर्शित किया जा सके। एकीकृत पवेलियन में विभिन्न खनन परियोजनाओं, खनन और सुरंग निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एनआईआरएम की भूमिका से संबंधित डिजिटल डिस्प्ले और मॉडल थे।कार्यक्रम स्थल पर मौजूद वैज्ञानिकों की गहरी भागीदारी ने बच्चों,पुरुषों और महिलाओं और सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के बीच व्यापक रुचि जगाई।

माननीय खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में आईआईटीF 2025 में माइनिंग पवेलियन में एनआईआरएम स्टॉल का दौरा किया, उनके साथ खान मंत्रालय के सचिव श्री पीयूष गोयल, IAS और खान मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती फरीदा एम नाइक भी थीं। एनआईआरएम के निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) डॉ. श्रीपाद आर नाइक डिस्प्ले और गतिविधियों के बारे में समझाते हुए दिखे।

विविध:-

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीF) 2025

(i) खान मंत्रालय के पवेलियन ने आईआईटीF 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों के पवेलियन श्रेणी के तहत डिस्प्ले में उत्कृष्टता के लिए रजत पदक (दूसरा पुरस्कार) जीता। "एक भारत,

श्रेष्ठ भारत" थीम के अनुरूप, पवेलियन ने एक लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया और भारत की खनिज संपदा, तकनीकी नवाचार, स्थिरता प्रयासों, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया।

(ii) पवेलियन का मुख्य आकर्षण सामुदायिक सशक्तिकरण था। विभिन्न राज्यों के जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) समर्थित स्वयं सहायता समूह (SHG) बांस के शिल्प, हस्तनिर्मित सामान और क्षेत्रीय विशेष उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे थे। पवेलियन ने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक जुड़ाव को एक साथ लाया, जिससे आईआईटीF 2025 में सार्वजनिक बातचीत और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ।

विशेष अभियान 5.0:-

खान मंत्रालय ने अपने संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, CPSEs और स्वायत्त निकायों के साथ मिलकर विशेष अभियान 5.0 को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसका उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना, सांसदों, PMO, IMC और राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों के लंबित मामलों को कम करना, सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना और प्रभावी स्क्रैप निपटान सुनिश्चित करना था। पिछले अभियानों की गति को जारी रखते हुए, मंत्रालय ने अभियान के दौरान अपने 100% लक्ष्य हासिल किए।

अभियान के दौरान, 578 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹97 लाख का स्क्रैप निपटाया गया और लगभग 48,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ। 6,700 से अधिक फाइलों को हटाया गया, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यक्षेत्र अनुकूलन में काफी सुधार हुआ। सभी संदर्भों और शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया, और काम करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए 11 नियमों को सरल बनाया गया। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि JNRDDC (**जे एन ए आर डी डी सी)** द्वारा 58 स्थानों पर समन्वित राष्ट्रव्यापी घरेलू ई-कचरा रीसाइक्लिंग अभियान चलाया गया, जिसने अधिकृत रीसाइक्लर्स के माध्यम से 9.02 टन ई-कचरा एकत्र किया, जिससे ₹11 लाख से अधिक की आय हुई और टिकाऊ, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को मजबूत किया गया।

स्वच्छता ही सेवा (एस एच एस) अभियान 2025

खान मंत्रालय ने अपने फील्ड संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 'पूरी सरकार' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्वच्छता ही सेवा (एस एच एस) अभियान 2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान में 5,853 अधिकारियों ने भाग लिया और 98 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सी टी यू एस) को सफलतापूर्वक बदला गया। खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल ने खनिज कक्ष, शास्त्री भवन में स्वच्छता की शपथ दिलाई, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इंडिया गेट से शास्त्री भवन तक एक मानव श्रृंखला बनाई, जिससे सामूहिक जिम्मेदारी के संदेश को मजबूत किया गया। "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" के आह्वान के तहत, वरिष्ठ अधिकारियों ने शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान में भाग लिया।

अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने सफाई मित्रों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्वच्छता में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई। स्वच्छता कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया, प्रशंसा के प्रतीक के रूप में जूते वितरित किए गए, और सफाई मित्रों और मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। वेस्ट टू वेल्थ की कहानी को और मजबूत करते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद में वेस्ट टू वेल्थ मॉडल का उद्घाटन किया और स्वच्छता किट वितरित कीं।

******